सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 196, नई दिल्ली । बुधवार, 25 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया, वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब कराती है।

03 अब दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी के जरिए होगा किडनी ट्रांसप्लांट...
06 कायम रहे 'नीट युजी' की व्यवस्था
08 डाल लदे ट्रक में लगी आग

भारत देश की राजधानी दिल्ली जहां विश्व की महिलाएं आती है में सार्वजानिक सवारी वाहनों में महिला सुरक्षा आवश्यक है या आईएएस शहजाद आलम का महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हो रहे कार्यों को बंद करने का दिया गया तर्क. जाने पूरा विवरण

क्या निर्भया कांड जैसी दुर्घटना वाहनों में ना हो उसके लिए शुरू की गई पुलिस वेरिफिकेशन का उच्च न्यायालय और गृह सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी का निर्णय गलत है, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की जनता को खास तौर से महिलाओं को सार्वजनिक सवारी वाहनों में सुखद, सुरक्षित महसूस रहे और वह निडर निर्भीक होकर 12 महीने 24 घंटे में कभी भी कहीं भी आने और जानें में कोई भय महसूस नहीं करे इसके लिए दिल्ली में घटित निर्भया कांड के बाद ही भारत सरकार के गृह सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी जिसने इस बाबत बड़े सख्त दिशा निर्देशों की बात कही थी जिसमें सबसे प्रमुख था *दिल्ली में जितने भी वाहन सार्वजनिक सवारी सेवा में पंजीकृत हैं उन सभी के मालिकों के निवास स्थान और उनका चरित्र का दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच शाखा द्वारा जांच करवाई जाए और गलत सूचना देने वाले और गलत चरित्र वाले मालिकों के वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाए और उन पर कानून के तहत कार्यवाही की जाए साथ ही नए वाहनों के पंजीकरण करने से पहले हर हालात में उसके द्वारा दिए जा रहे एड्रेस और चरित्र की जांच दिल्ली पुलिस से करवाई जानी अनिवार्य है और पुलिस वेरिफिकेशन लिए बिना वाहन पंजीकृत ना किया जाए और ना मानने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय दिल्ली में एक क्रिमनल रिट पर जज उषा मेहरा ने भी सख्त निर्देश जारी कर पुलिस वेरीफिकेशन के बिना पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।

इसके अलावा व्यावसायिक सार्वजनिक सवारी वाहनों में सीसी टीवी कैमरे और पैनिक बटन अनिवार्य किए थे।

पिछले महीने तक सचिव एसटीए के पद पर आसीन विशेष परिवहन आयुक्त ने अलग अलग क्वेरी के नाम से वाहनों में पैनिक बटन पर निगरानी करने के लिए आवश्यक डाटा बेस सेंटर को शुरु ही नहीं होने दे रहे थे जब की कमेटी और उच्च न्यायालय की आखों में धूल झोंकने के लिए आदेश के प्रथम दिन से ही वाहन मालिकों से बिना निगरानी डाटा सेंटर के भी प्रति माह फीस लेना शुरु कर दिया था।

यह सभी तथ्य महिला सुरक्षा से जुड़े हैं इसलिए आपको अब हम जो अवगत करवा रहें हैं उसको जानने के बाद आप समझ जाएंगे की **विशेष परिवहन आयुक्त आईएएस शहजाद आलम को दिल्ली में चालित सार्वजानिक सवारी वाहनों में महिला सुरक्षा की जरा सी भी जरूरत महसूस नहीं होती है और उनके अनुसार विभाग द्वारा वाहन के पंजीकरण के समय वाहन मालिक से पुलिस वेरीफिकेशन वह भी साफ बिना किसी केस के मांगना वाहन मालिक को परेशान करना है।** गृह मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी और जज साहिबा उषा मेहरा का निर्णय इन्हे गलत लगता है **अब दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार, परिवहन आयुक्त, मुख्य सचिव दिल्ली, उपराज्यपाल दिल्ली, गृह मंत्री भारत सरकार कृप्या करके बताए की भारत देश की राजधानी जहां विश्व की महिलाएं आती है में सार्वजानिक सवारी वाहनों में महिला सुरक्षा आवश्यक है या आईएएस शहजाद आलम का महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हो रहे कार्यों को बंद करने का दिया गया तर्क.**

मेट्रो की 'ब्लू लाइन पर हमें रोज-रोज...' यात्रियों ने DMRC से कर दी बड़ी डिमांड

राजधानी दिल्ली और एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के यात्रियों ने पोस्ट कर DMRC से बड़ी मांग की है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यात्रियों ने लिखा कि ब्लू लाइन पर ऑफिस के समय व्यस्त समय में मेट्रो देरी से उपलब्ध होती है। साथ ही इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है।

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन बनकर उभरी दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन जैसे व्यस्त कॉरिडोर पर देर से मेट्रो उपलब्ध होना यात्रियों को परेशान करने लगा है। इस वजह से कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ब्लू लाइन पर ऑफिस के वक्त व्यस्त समय में मेट्रो विलंब से उपलब्ध होने की दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) से शिकायत की।

दो मिनट के अंतराल पर मेट्रो परियोजना सुनिश्चित करने की मांग

इसके साथ ही ब्लू लाइन (Delhi Metro Blue Line) के पूरे हिस्से पर दो मिनट के अंतराल पर मेट्रो परियोजना सुनिश्चित करने की मांग की। ताकि व्यस्त समय में यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो।

सैयद हिफजुर नामक एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेट्रो में सफर करने वाले यात्री बहुत समस्या झेल रहे हैं।

ऑफिस जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी- शिकायत

इससे ऑफिस जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। डीएमआरसी इस समस्या का निदान करे। सुबह व्यस्त समय में 9.24 बजे किए गए इस पोस्ट में उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें यात्री सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर द्वारका के लिए आठ मिनट पर मेट्रो उपलब्ध होने की सूचना प्रदर्शित हो रही है।

प्रिंस नामक एक यात्री ने अपने पोस्ट में कहा कि ब्लू लाइन की मेट्रो में बहुत भीड़ है। सरकार को दो मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलाना चाहिए। अभी पांच से आठ मिनट के अंतराल पर मेट्रो चल रही है।

न्याय चक्र वेलफेयर एसोसिएशन ने बुराड़ी ऑथोरिटी को बुराड़ी में ही पुनः स्थापित करने के संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपरोक्त विषय से आपको अवगत कराना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी और गैर मौजूदगी में सरकार ने ऑटो चालकों के लिए बहुत सारे अच्छे फैसले लिए और काफी अच्छे कार्य किए परंतु परिवहन विभाग के कुछ गलत फैसले की वजह से चालक बहुत ही परेशान है और सरकार से नाराज़ हैं, हमें लगता है कि परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों ने मिलि भगत करके विपक्षियों को मौका देने व सरकार की ओर से ऑटो व टैक्सी ट्रांसपोर्टरों का मोह भंग करने की साज़िश कर रहे है।

महाशयाः- ज्ञात हो कि बुराड़ी ऑथोरिटी विगत 30, 35 वर्षों से एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर ऑटो व टैक्सी के लिए अधिकृत था और स्वतंत्र रूप से उनसे संबंधित सभी कार्य कर रहा था परन्तु कुछ महीने पहले पूर्व

मुख्यमंत्री जी के गैर मौजूदगी में परिवहन विभाग के कुछ आला अधिकारियों ने बुराड़ी इकाई को भंग करके कागजी कार्यवाही को राज पुर रोड हस्तांतरित कर दिया व ऑटो फिटनेस ग्राउंड को कलेक्टर बस चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्वाइंट बना दिया और ऑटो फिटनेस पीट को वहां से हटा दिया है।

महोदयाः- जबसे ऑथोरिटी को बुराड़ी से राजपुर रोड हस्तांतरित किया गया है तबसे ऑटो और टैक्सी चालकों का काम लगभग हो ही नहीं रहा है सभी ट्रांसपोर्टर परेशान है और सरकार के प्रति रोश व्यक्त कर रहे है। परिवहन विभाग ने ऑटो टैक्सी चालकों के कार्य करने के लिए दो इंस्पेक्टर असत्रव वाजपेयी और योगेश यादव को नियुक्त किया है, वो दोनों ही, भ्रष्ट मानसिकता से ग्रस्त है और कोई काम ही नहीं कर रहे है, चालक त्राहि माम त्राहि माम कर रहा है। उधर ऑटो फिटनेस ग्राउंड को कलेक्टर बस चार्जिंग के लिए देकर ऑटो फिटनेस पीट को जे बी एम ग्लोबल नामक कंपनी को दे दिया गया है, जिसको विपक्षी घोटाला से जोड़ कर मुद्दा बना रहे है और चालको को गुमराह कर अपने पक्ष में ले रहे। महोदया, ये हमारा भी मानना है कि कलेक्टर बस चार्जिंग के लिए कंपनी स्वयं अपना जगह ले सकती है अथवा सरकार उन्हें, और, कही जगह दे सकती थी या दे सकती है, उसके लिए ऑटो

फिटनेस पीट को विस्थापित करने व इकाई को भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस पर अविलंब विचार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री महोदया, हम सरकार की किसी भी तरह का विरोध नही कर रहे है, बल्कि विचार करने का आग्रह कर रहे है और इससे हो रहे नुकसान से अवगत कराने की प्रयास कर रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर से विचार करें व यथा संभवतः बुराड़ी ऑथोरिटी को इकाई के तौर पर पूर्व के भांति पूनरः स्थापित कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

सुभाष कुमार सुभाष कुमार
सचिव, न्याय चक्र वेलफेयर एसोसिएशन।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली में सड़क सुरक्षा: समस्या और समाधान

दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं की संख्या अब केवल एक संख्या नहीं रह गई है; यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हाल के वर्षों में, दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2022 में, दिल्ली में 6,300 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 1,400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि सड़क सुरक्षा की स्थिति कितनी गंभीर है।

दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण

एक प्रमुख कारण यह है कि दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों की नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 से रात 11 बजे तक वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश निषेध है। लेकिन जब ये वाहन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना लगभग 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है, जो ड्राइवर और वाहन मालिक दोनों पर लगाया जाता है। यह जुर्माना इतना अधिक है कि कई ड्राइवर बिना सोचे-समझे अपने वाहनों को कहीं भी खड़ा कर देते हैं, जिससे सड़कें जाम होती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं।

अव्यवस्थित पार्किंग का प्रभाव

दिल्ली में अव्यवस्थित पार्किंग भी एक गंभीर समस्या है। 500 रुपये के छोटे जुर्माने की तुलना में, नो एंट्री का जुर्माना अत्यधिक है, जिसके कारण ड्राइवर अनियंत्रित तरीके से अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। इस स्थिति में न केवल यातायात में रुकावट आती है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। 2022 में रिपोर्ट की गई 1,400 मौतों में से कई अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक जाम के कारण हुईं।

सरकार की भूमिका और कमी

सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने में विफलता साफ दिखाई देती है। सड़कें चौड़ी करने और ट्रैफिक सिग्नल लगाने के बजाय, सरकार ने अधिकतर वाहनों पर जुर्माने लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। क्या केवल जुर्माना लगाकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? यह सवाल है जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जब तक सही उपायों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंकड़े केवल बढ़ते रहेंगे।

सुझाव और समाधान

रात में वाणिज्यिक वाहनों की अनुमतिः दिल्ली में भारी वाणिज्यिक वाहनों की रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक केवल अनुमति दी जानी चाहिए। इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

कच्चे माल और चिकित्सा ऑक्सीजन वाहनों को दिन में अनुमतिः कच्चे माल और चिकित्सा ऑक्सीजन के वाहनों को दिन में विशेष अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा न आए।

जुर्माने में समुचित बदलावः नो एंट्री के जुर्माने को पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर, अव्यवस्थित पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि चालक अव्यवस्थित पार्किंग से बचें।

जन जागरूकता अभियानः सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। लोगों को सुरक्षित यातायात के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियमों का सही पालन और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार से न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, बल्कि लोगों की जानें भी बचाई जा सकती हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सरकार को चाहिए कि वे इस दिशा में सख्त कदम उठाएं ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें। यह केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे।

जगमोहन सिंह
रोड सेफ्टी
ओम्नी फाउंडेशन

इनसाइड

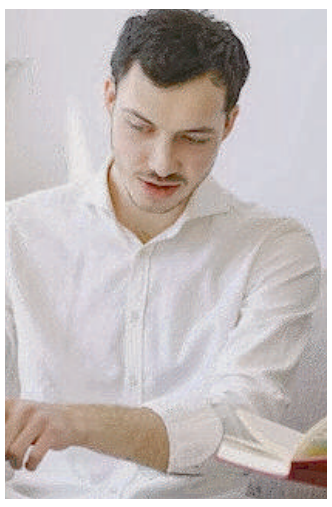

ऑफिस में महिला कलीग से बात करें तो जरूर रखें इन बातों का ख्याल, बन जाएंगे उनके फेवरेट, बॉन्डिंग भी होगी स्ट्रॉन्ग

ऑफिस में फीमेल कलीग से बात करना कई पुरुषों के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में पुरुष महिला कलीग के सामने भाषा पर ध्यान देने से लेकर स्माइल करने, मोटिवेट रखने जैसे कुछ टिप्स अपनाकर उनके साथ हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं.

ऑफिस में पुरुष और महिला कलीग्स दोनों मौजूद रहते हैं. ऐसे में कई मेल कलीग्स आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं मगर फीमेल कलीग्स के सामने ज्यादातर पुरुष असहज महसूस करते हैं. आप चाहें तो महिला सहकर्मी से बात करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखकर ना सिर्फ उनके फेवरेट बन सकते हैं, बल्कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

फीमेल कलीग के सामने कई सारे पुरुष नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते वे महिलाओं से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप फीमेल कलीग्स से बेस्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफिस में महिला कलीग से बात करने के टिप्स.

भाषा पर संयम रखें

अपने ऑफिस की किसी भी महिला कर्मचारी से बात करते समय पुरुषों को भाषा पर ध्यान देना जरूरी होता है. दरअसल, पुरुष आपस में तुम या तू करके बात करते हैं मगर महिलाओं के सामने ऐसे पेश आने से आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है. वहीं, फीमेल कलीग के सामने बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें, जिससे वे भी आपके सामने सहज महसूस कर सकें.

स्माइल करना है जरूरी

अगर आप महिला कलीग से बात करने में असहज महसूस करते हैं तो आप उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं. फीमेल कलीग से आई कॉन्टैक्ट होने पर आपकी एक मुस्कान भी काफी है. इससे आप बिना बोले उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होने लगेगा.

काम पर ध्यान दें

महिला कलीग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप काम में उनकी मदद मांग सकते हैं. इससे ना सिर्फ ऑफिस का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, बल्कि काम के बीच में हंसी-मजाक करने से आपका रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा. लेकिन, काम के दौरान पॉजिटिविटी बरकरार रखें और साथी कलीग की बुराई करने से बचें.

मोटिवेट करें

महिला कलीग को काम के प्रति मोटिवेट रखकर आप उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं. इससे फीमेल कलीग की ऑफिस परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगेगी. साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप फीमेल कलीग के फेवरेट बन जाएंगे.

टी ब्रेक पर जाएं

ऑफिस के काम में लोगों को फीमेल कलीग से बात करने का मौका कम ही मिलता है. ऐसे में आप महिला कलीग को चाय या कॉफी का ऑफर दे सकते हैं मगर ध्यान रहे कि हर रोज महिला कलीग के साथ टी ब्रेक पर ना जाएं. इससे फीमेल कलीग के साथ आप बेस्ट प्रोफेशनल रिलेशन बना सकेंगे.

कस्तूरबा गांधी: बापू से लड़ीं-तर्क किए

नहीं माना मनमाना आदेश, पर हर फैसले में साथ रहीं, उजागर नहीं किए मतभेद

कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के सत्याग्रह समर्पण और त्याग में बराबर की सहभागी बनी। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। महान बने, देशवासियों के लिए भगवान बने। राष्ट्रपिता कहलाए, शांति और आजादी के दूत बने, लेकिन क्या यह सब उन्होंने अकेले अपने दम पर हासिल किया या फिर कोई मजबूत सहारा बन सालों साल खड़ा रहा?

इसके जवाब में एक नाम है- कस्तूरबा गांधी। यह वही नाम है, जो गांधी के सत्याग्रह, समर्पण और त्याग में बराबर का सहभागी बना। उनके हर कदम का साथी बना। तर्क-वितर्क किया, लेकिन हर फैसले को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

आज कस्तूरबा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर पढ़िए कि 'बा' क्या थीं- एक घरेलू महिला या महिला सशक्तिकरण की मिसाल...

कस्तूरबा गांधी के जीवन पर किताब 'द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा' लिखने वाली लेखिका नीलिमा डालमिया आधार कहती हैं कि 'बा' बेहद पारंपरिक और पतिव्रता स्त्री थीं। शादी से लेकर आखिरी सांस तक गांधी के हर फैसले में साथ खड़ी रहीं। अच्छी पत्नी और मां बनने की कसौटी पर खरी उतरने में लगी रहीं।

घर संभाला, आश्रम संभाले। न सिर्फ अपने बच्चों, बल्कि आंदोलनकारियों पर भी ममता लुटाई। बा ने गांधी जी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को और मजबूत बनाया। महिलाओं को इसमें जोड़ा, जिससे हिंदुस्तान का घर-घर आजादी के इस आंदोलन से जुड़ा।

नीलिमा कहती हैं कि जब मैंने शोध किया तो हैरान रह गई। कस्तूरबा के बारे में सब सोचते हैं कि वह एक घरेलू महिला थीं, जो सिर्फ अपने पति का अनुसरण करती थी, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी, जबकि वे इसके बिल्कुल विपरीत थीं। वह बहुत आत्मनिर्भर और साहसी महिला थीं, जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं।

वक्त के सितम भी सहे...

वह आगे बताती हैं कि आज ही के दिन, यानी 11 अप्रैल, 1869 में उनका जन्म हुआ। कस्तूरबा एक बेहद धनी परिवार की बेटी थी। उनके पिता पोरबंदर के पूर्व मेयर गोकुलदास मकनजी कपाड़िया बेहद सम्मानित व्यापारी थे, जिनका विदेशों में कपड़े, अनाज और कॉटन का व्यापार था। समुद्र में उनके जहाज चलते थे। चार भाइयों की इकलौती बहन थीं। बहुत लाड-प्यार से पली-बढ़ीं, लेकिन गांधी परिवार में आने के बाद वक्त और गांधी दोनों के अत्याचार सहने पड़े।

जब 13 साल की उम्र में शादी कर मोहनदास की पत्नी बनी, तब कस्तूरबा मन से चंचल, लेकिन स्वभाव से समझदार व समर्पित पत्नी थीं। इसके इतर, गांधी बेहद डोमिनेटिंग एंड पजेसिव हजबैंड थे। वे कस्तूरबा को अपने मुताबिक चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाते। गांधी ने कस्तूरबा को आदेश दिया था कि वे बिना उनसे पूछे न कहीं जाएंगी और न कोई काम करेंगी, लेकिन कस्तूरबा ने गांधी के इस आदेश को नहीं माना। इससे चिढ़ कर गांधी कस्तूरबा के प्रति और कठोर हो गए।

गांधी के मनमाने आदेश को नहीं माना..

'सत्य के प्रयोग' में गांधी ने इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है, 'मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना है तो पत्नी को एक पति व्रत का पालन करना चाहिए, यह सोचकर मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालन चाहिए से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर चल पड़ा और मैंने पत्नी की निगरानी शुरू कर दी।

मैं सोचता... मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहां जाती है और क्यों? मेरी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती, लेकिन कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती, वहां मुझसे बिना पूछे जरूर जातीं। मैं जैसे-जैसे दबाव डालता, वैसे-वैसे वह अधिक आजादी से काम लेतीं और उतना ही मैं ज्यादा चिढ़ता।' हालांकि, बाद में गांधीजी ने कहा कि जैसे-जैसे मैं कस्तूरबा को जानता गया, वैसे-वैसे उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया और उनका ज्यादा सम्मान करने लगा।

जब बा ने गांधी से कहा- तुम्हें थोड़ी शरम नहीं आती

साउथ अफ्रीका में गांधी जी स्वावलंबन को आगे बढ़ा

रहे थे। घर में नौकर नहीं थे। सभी को अपने काम स्वयं करने होते थे। उस वक्त अभी जैसे टॉयलेट नहीं होते थे, तब मैला खुद साफ कर फेंकना होता था। गांधी ने कस्तूरबा को अपने यहां आए मेहमान का मैला साफ करने को मजबूर किया तो वे गुस्से से फट पड़ी। कहा- बहुत हो चुका, अब वे नहीं करेंगी। इसके बाद दोनों के बीच बुरी तरह झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गांधी कस्तूरबा को बांह पकड़ कर घर से बाहर निकालने लगे। इसके बाद बापू अपने किए शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने चेहरे पर सख्ती लाता हुए दरवाजा बंद कर दिया।

गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, "यह बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मुझे एक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाला था। कस्तूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्ला रहीं थी कि तुम्हें थोड़ी भी लाज शरम नहीं है? तुम अपने आप को इतना भूल गए? मैं कहां जाऊंगी? तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीवी रहते हुए मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हारी ठोकरें खाने के लिए हूं। भगवान के लिए अपना व्यवहार ठीक करो और गेट को बंद कर दो। इस तरह का तमाशा मत खड़ा करो।"

गांधी से लड़ीं, तर्क किए पर साथ नहीं छोड़ा

लेखिका नीलिमा डालमिया आगे बताती हैं कि कई जगहों पर कस्तूरबा और गांधी जी के विचार एक-दूसरे से नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में वह विरोध भी करतीं और अपने तर्क रखतीं। इसके बावजूद वह गांधी के साथ अडिग खड़ी रहतीं। गांधी जी ने कई ऐसे फैसले किए जो अमान्य हो सकते थे, लेकिन बा ने उन्हें माना और गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। मां और पत्नी के रूप में वह हमेशा समर्पित मनस्थिति में रहीं।

गांधी जी की बेटों के प्रति विचारों की असहमति का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के साथ नाम जुड़ने का उन्होंने दोनों पर तक किए, लेकिन कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच मतभेद भी होते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी बाहर नहीं आने दिया। हर फैसले में गांधी का साथ दिया।

अधिकार जताया, पर शक नहीं किया

आश्रम में गांधी महिलाओं के इर्द गिर्द घिरे रहते, लेकिन कस्तूरबा के मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ। नीलिमा एक किस्सा सुनाती हैं, जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तब कैंप में वे बीमार पड़ गए। उस वक्त एक ब्रिटिश महिला मीरा बेन गांधी की विशेष अनुयायी हुआ करती थी। मीरा बेन ने कहा कि गांधी जी उनके साथ रहेंगे ताकि वे अच्छे से देखरेख कर सकें। उस वक्त 'बा' ने अपना अधिकार जताया। कहा- नहीं, वो मेरे साथ रहेंगे और मैं उनका ख्याल रखूंगी।

इसी तरह जब सरला देवी से गांधी का नाम जुड़ा तो उनके करीबी भी चिंतित हो उठे। सबको लगा कि गांधी ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़कर सरला से शादी तो नहीं कर लेंगे! गांधी के पोते तुषार ने एक इंटरव्यू में बताया कि बापू के करीबी लोग कस्तूरबा के पास पहुंचे और उनसे गांधी को समझाने की गुजारिश करने लगे, तब बा ने कहा, "तुम मेरे पति को पहचानते नहीं हो। मेरे पति को जो मुझमें नहीं मिल रहा है, वह दूसरों में ढूढ़ रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो कहीं नहीं जाएंगे।"

गांधी को बापू बनाने वाली सशक्त महिला

लेखिका बताती हैं कि एक बार की बात है, जब कस्तूरबा कलकत्ता (अब कोलकाता) में हरिलाल के दूसरे बेटे के जन्म के मौके पर गई थीं, तभी गांधी बीमार हो गए। जब कस्तूरबा को इसका पता चला तो वह लौट आईं। कस्तूरबा को देखकर गांधी जी बिलख पड़े और बोले कि तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। दोनों के बीच प्रेम था। कस्तूरबा में पति के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी।

कस्तूरबा ने अपनी आखिरी सांस पुणे की आगाखान डिटेंसन कैंप में बापू की गोद में ली। जब बा का अंतिम संस्कार किया गया तो गांधी वहां तब बैठे रहे, तब तक चिता पूरी नहीं जल गई। जब चिता जल रही थी और गांधी शांत भाव से खड़े-खड़े देख रहे थे, तब किसी ने गांधी जी से कहा- कब तक खड़े रहेंगे थक जाएंगे। तब बापू ने जवाब दिया, '62 साल के साथी को क्या इस तरह छोड़ सकता हूं, यह अंतिम विदाई है। इसके लिए तो बा भी मुझे माफ नहीं करेगी।

गांधी के जीवन में छोड़ गई सूनापन

गांधी ने लिखा, 'बा को हमेशा ये अहसास रहा कि अगर वह चली जाएंगी तो मैं टूट जाउंगा। अगर बा का साथ न होता तो मैं इतना ऊंचा उठ ही नहीं सकता था। यह बा ही थीं, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। नहीं तो भगवान जाने क्या ही होता? मेरी पत्नी मेरे अंतः को जिस प्रकार हिलाती थी, उस प्रकार दुनिया की कोई स्त्री नहीं हिला सकती। वह मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थीं, उनके जाने से जो सूनापन पैदा हो गया है, वह कभी भर नहीं सकता।'

लूज हो रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस? महिलाएं इन 7 टिप्स की लें मदद, दमदार बन जाएगी पर्सनैलिटी

जिंदगी में सफल और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी होता है. हालांकि कुछ लोगों में कॉन्फीडेंस का लेवल अक्सर कम रहता है. ऐसे में ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने से लेकर खुद पर विश्वास रखने और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

शानदार पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस हाई होना बेहद जरूरी होता है. खासकर करियर को बेहतर बनाने में आत्मविश्वास का अहम योगदान होता है. हालांकि कुछ लोगों में अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस (Self confidence) की कमी देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है. तो आप कुछ आसान टिप्स की मदद ले सकते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास मिनटों में बढ़ता दिखाई देने लगेगा.

सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करता है. ऐसे में आत्मविश्वास को ज्यादातर लोगों का हैप्पीनेस सीक्रेट भी माना जाता है. वहीं कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण लोगों को लाइफ में काफी सफर करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के कुछ आसान टिप्स, जिसकी मदद से आप खुशमिजाज और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करें

ड्रेसिंग सेंस आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है. ऐसे में अच्छी ड्रेस, मैचिंग फुटवियर और गुड लुक कैरी करके आप अंदर से काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं.

कम्युनिकेशन पर ध्यान दें

कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसे में अलग-अलग लोगों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करें. इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे.

खुद पर विश्वास रखें

खुद पर भरोसा ना होने पर लोग अक्सर कन्फ्यूज और डल महसूस करते हैं. ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना जरूरी होता है. इसलिए दूसरों की बातों पर गौर करने की बजाए अपने फैसलों का सम्मान करें.

गलतियों से ना डरें

गलतियों के डर से लोग अक्सर कुछ नया करना अवॉइड कर देते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है. ऐसे में आलोचनाओं का डट कर सामना करें और हमेशा नया सीखने के प्रति तत्पर रहें. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

दूसरों से अलग बनें

कई बार दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में लोग अपनी यूनीक पर्सनैलिटी से समझौता कर लेते हैं. हालांकि खुद को दूसरों से अलग बनाकर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं. इसलिए किसी को कॉपी करने की बजाए अपनी स्किल्स को निखारने पर फोकस करें.

डर से लड़ें

कई बार हार या आलोचनाओं के डर से लोग अपने दिल की नहीं सुनते हैं. जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते हैं. इसलिए डर से भागने की बजाए इसका डट कर सामना करें और अपनी बात रखने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं. इससे आपका कॉन्फिडेंस आसानी से बूस्ट होने लगेगा.

लोगों की बातों को करें नजरअंदाज

कुछ लोग दूसरों की बातों को अक्सर दिल से लगा लेते हैं. जिससे आप खुद अपनी सफलता में बाधक बन जाते हैं. इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें और खुद अपनी गलतियों से सीख लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें. इससे आप कॉन्फीडेंट और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे.

50 के बाद भी रहना है हेल्दी, 4 विटामिन्स को करें डाइट में शामिल, कम दिखने लगेगी उम्र, हमेशा रहेंगी फिट

पचास की उम्र के बाद महिलाओं में कमजोरी आने लगती है. ऐसे में महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र को कम दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं. वहीं, तमाम नुस्खे आजमाने के बाद भी महिलाएं अपनी ऐज को छुपाने में नाकाम हो जाती हैं. अगर आप 50 की हो रही हैं तो कुछ जरूरी विटामिन्स को डाइट (Diet tips) में एड करके आप उम्र के असर को आसानी से हाइड कर सकती हैं.

50 प्लस वुमेंस में विटामिन की कमी होना काफी आम बात है. ऐसे में विटामिन रिच डाइट को अवॉयड करने से ना सिर्फ महिलाएं फिजिकली वीक महसूस करने लगती हैं, बल्कि आपकी उम्र भी ज्यादा दिखती है. मेडिकलन्यूज़टुडे के मुताबिक, हम आपको बताते हैं 5 एसेंशियल विटामिन सप्लीमेंट्स के नाम, जिनका सेवन करके आप 50 के बाद भी खुद को यंग रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 को एनर्जी का बेस्ट सोर्स माना जाता है. मगर बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलने लगती है. ऐसे में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, अंडा, मीट और खमीर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके आप विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

कैल्शियम रिच डाइट हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने से महिलाओं में फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है. ऐसे में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, बीन्स, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन और टोफू का सेवन कर सकती हैं.

विटामिन डी

50 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए विटामिन डी का सेवन भी जरूरी होता है. विटामिन डी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकान को दूर रखने में सहायक होता है. वहीं डेयरी प्रोडक्ट, अंडा और फिश को विटामिन डी का बेहतर स्रोत माना जाता है. इसके अलावा बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप कुछ देर धूप में भी बैठ सकती हैं.

विटामिन बी 6

50 के बाद शरीर में विटामिन बी 6 की कमी होने लगती है. ऐसे में फिट और हेल्दी रहने के लिए विटामिन बी 6 से भरपूर आहार लेना जरूरी हो जाता है. वहीं गाजर, पालक, केला, दूध, चिकन और कलोंजी को विटामिन बी 6 का बेस्ट सोर्स माना जाता है.

केजरीवाल दे रहे मुफ्त बिजली और भाजपा दे रही महंगी: संजय सिंह

दिल्ली सरकार ने भाजपा शासित राज्यों में बिजली की ऊंची दरों पर सवाल उठाए हैं। सदस्य संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं जबकि भाजपा बिजली के नाम पर जनता से लूट रही है। उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान में अदाणी को बिजली आपूर्ति के लिए दिए गए टेंडर पर भी सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित राज्यों में जनता को मिल रही बिजली को लेकर भाजपा नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा बिजली के नाम पर जनता से खुली लूट की छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि आदेश को दरकिनार कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने सोलर और कोयले से बनी बिजली लेने के लिए मिक्स टेंडर निकाला और ऐसी कंडीशन लगा दी कि वहां अदाणी को 6600 यूनिट बिजली आपूर्ति करने का टेंडर दे दिया।

राजस्थान में भी महंगी बिजली

उन्होंने कहा कि वहीं राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी 11200 यूनिट बिजली के लिए अदाणी से पहले एमओयू साइन कराया और इसके बाद मिक्स टेंडर निकाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां भी ऐसी कंडीशन लगा दी गई हैं कि यह टेंडर भी अदाणी को ही मिलेगा।

अब दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी के जरिए होगा किडनी ट्रांसप्लांट, AIIMS में अमेरिका से आएंगी अत्याधुनिक मशीनें

दिल्ली में एम्स के सर्जिकल ब्लाक व कैंसर सेंटर सहित कई विभाग में रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है। अगले महीने मशीनें लगा दी जाएंगी। ये मशीनें अमेरिका से आएंगी। एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मशीनें लगने के बाद रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी प्रत्यारोपण होने लगेगा।

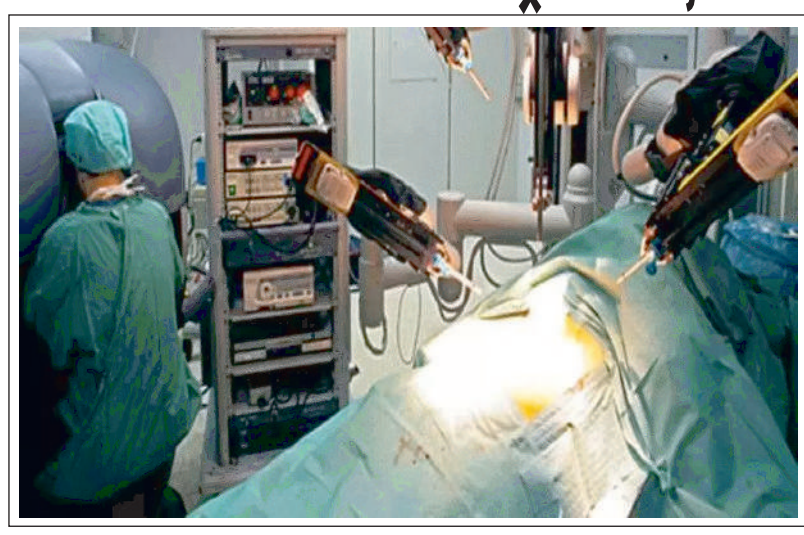

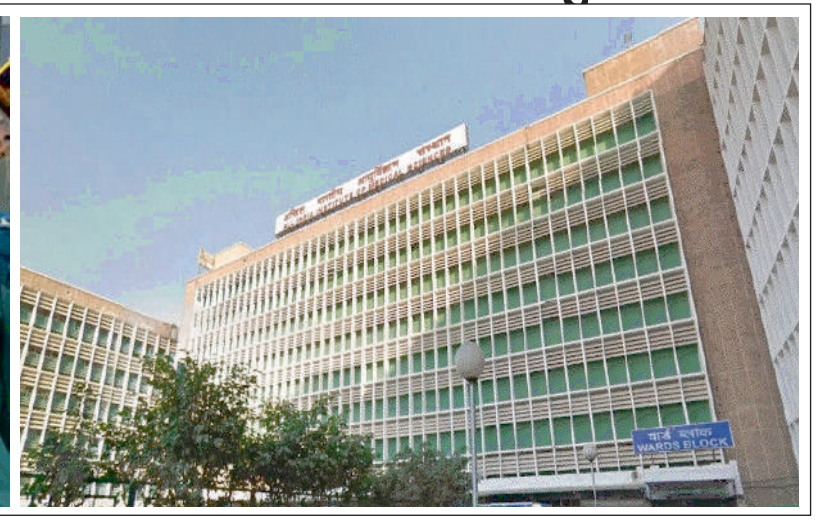

नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के सर्जिकल ब्लाक, कैंसर सेंटर सहित कई अन्य विभागों के ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी है। सर्जिकल ब्लाक में अगले माह अत्याधुनिक रोबोटिक लग भी जाएगी। तब एम्स में रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी प्रत्यारोपण होने लगेगा। वहीं, मंगलवार को रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में एम्स के जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. वीके बंसल ने यह जानकारी दी।

एम्स में अभी दो रोबोटिक मशीन पहले से मौजूद है। जिसमें से एक रोबोटिक मशीन मुख्य अस्पताल व दूसरी मशीन आर्थोपेटिक विभाग की ओटी में लगी है। सर्जिकल ब्लाक में अभी रोबोटिक मशीन नहीं है। इस वजह से जनरल सर्जरी विभाग से संबंधित मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है।

डॉ. वीके बंसल ने बताया कि रोबोटिक मशीन से सर्जरी ज्यादा सटीक होती है। जटिल सर्जरी भी बगैर बड़े चीरा लगाए छोटे-छोटे छेद कर रोबोटिक मशीन से हो जाती है। इससे मरीज जल्दी ठीक होकर अपने काम पर लौट पाते हैं।

अमेरिका की कंपनी मुफ्त देगी रोबोटिक मशीन

एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत अमेरिकी कंपनी रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए एम्स को करीब 16 करोड़ की रोबोटिक मशीन मुफ्त देगी। इससे संस्थान में एम्स दा विंची रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा।

एम्स में रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए दो अन्य कंपनियों की मशीनें पहले से मौजूद हैं, जिसमें एक स्वदेशी तकनीक की मशीन भी शामिल है। डॉ. वीके बंसल ने बताया कि नई मशीन डेढ़ महीने में आ जाएगी। तब एम्स में रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर में मौजूद तीनों रोबोटिक प्लेटफार्म एम्स में उपलब्ध हो जाएगी।

डॉक्टरों को विदेश जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

बताया कि इससे डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजी अस्पतालों के डॉक्टर व दूसरे देशों के डॉक्टर भी यहां प्रशिक्षण ले सकेंगे। नर्सिंग व पैरामेडिकल कर्मचारी भी प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। एम्स में अब तक 200 डाक्टर रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से गायनी जरनल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी सहित सभी विभागों में रोबोटिक सर्जरी हो सकेगी। आगे चलकर मातृ एवं शिशु ब्लाक में भी रोबोटिक मशीन लग सकेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी।

दिल्ली में कानून-व्यवस्था के लिए LG का सख्त रवैया, कमिश्ननर से कहा- शहर में दिखनी चाहिए पर्याप्त पुलिस

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि शहर भर में पर्याप्त पुलिस की तैनाती दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त से वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार करने को भी कहा है जो निर्देशों के अनुपालन और शहर में पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही सादे कपड़ों में तैनात करने के लिए एक टीम का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहर भर में पर्याप्त पुलिस की तैनाती दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त से वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार करने को भी कहा है, जो निर्देशों के अनुपालन और शहर में पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसकी नियमित निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का ड्यूटी चार्ट, जिसमें उनकी तैनाती का विवरण और उनके फोन नंबर शामिल होंगे, राजनिवास को भेजा जाएगा।

पुलिस कर्मियों को तैनाती स्थल पर रहने को कहा

सक्सेना अपराध रोकने के लिए लगातार सड़कों, मोहल्लों और इलाकों में पुलिसकर्मियों के दिखाई देने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने पुलिस बीट/चौकियों के आसपास के क्षेत्रों में, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को साफतौर पर अपने तैनाती स्थल पर मौजूद रहने को कहा है। वह हमेशा इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की उपस्थिति स्वाभाविक तौर पर अपराध और अपराधियों को रोकती है।

यातायात पुलिस दिखने लगे

गौरतलब है कि एलजी ने जब से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और परिवहन अधिकारियों के साथ, साप्ताहिक आधार पर यातायात की स्थिति की समीक्षा करना शुरू किया है, तब से सड़कों पर यातायात पुलिसकर्मी अधिक संख्या में नजर आने लगे हैं।

सादे कपड़ों की टीम बनाने को कहा

सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाने की भी सलाह दी है, जो सादे कपड़ों में रहेगी और पुलिसकर्मियों की इलाके में उपस्थिति और निर्देशों के लागू होने को सुनिश्चित करेगी। एलजी ने साफ किया है कि इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।

"FLN" को सकारात्मकता के धरातल पर लाने के लिए पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय खिचडीपुर की मुख्य अध्यापिका" अनुपमा बिष्ट का एक प्रयास"

शम्स आगाज

नई दिल्ली : पी. एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर प्रथम पाली में 5 दिवसीय "FLN" कार्यशाला का आयोजन 19.9.24 से 24.9.24 तक किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्राचार्य अरविन्द कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर प्रथम दिन की "खेल एकीकृत शिक्षाशास्त्र" आधारित कार्यशाला शुरु की गयी। तत्पश्चात दूसरे दिन "कला एकीकृत शिक्षाशास्त्र" आधारित कार्यशाला, तीसरे दिन "अनुभवात्मक अधिगम शिक्षाशास्त्र" आधारित कार्यशाला, चौथे दिन "एफ एल एन संसाधन रखरखावर कार्यशाला तथा पाँचवे दिन "खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्रर कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

"FLN" कार्यक्रम में आनंद आधारित सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बच्चों को सीखने के लिए कहानी, गीत, नृत्य, TLM एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है। यह सब करने का उद्देश्य बच्चों में रूचि पैदा करके उन्हें विषय को बेहतर समझने के लिए प्रेरित करना होता है।

एफ एल एन के इसी सपने को साकार करने के लिए प्राथमिक विभाग की मुख्य अध्यापिका अनुपमा बिष्ट के नेतृत्व में प्राथमिक विभाग के सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी कर कार्यशाला को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शारदीय नवरात्र विशेष - सुख और समृद्धि की पालकी पर सवार होकर आ रही हैं माँ जगज्जननी : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना,

शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस साल गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है। जिसका समापन 11 अक्तूबर को नवमी के दिन होगा और 12 अक्तूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। सनातन धर्म में नौ दिनों की अवधि बहुत ही पवित्र मानी गई है। देवीपुराण के अनुसार गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का आगमन सुख और समृद्धि की पालकी से होता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना करने का विधान है। ताकि साधक और उसके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे।

शारदीय नवरात्र के शुभारम्भ के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुऐ वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। श्री खुराना ने आगे कहा कि भारतीय परम्परा में नवरात्रि का आयोजन देवी के नौ स्वरूपों के माध्यम से शक्ति, ज्ञान तथा ऐश्वरय के तीन महत्वपूर्ण पक्षो को प्रगट करता हैं। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा प्रतिमा और प्रति माँ में हैं। इसलिए समाज में देवी की प्रतीक महिलाओं के सम्मान के कार्यों को आगे बढ़ाएं, तो वे समाज में नई प्रेरणा बनेंगे। यह कार्य आधी आबादी को स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यह समाज व हम सब की जिम्मेदारी है और नवरात्र भी हमें जीवन में इस बात की प्रेरणा देते है कि कोई भी कार्य असम्भव नहीं है, बस बेहतर प्रयास की आवश्यकता है और आज प्रत्येक क्षेत्र में सम्भावनाएं हैं। उन सम्भावनाओं को समय से चुनते हुए कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह सभी कार्य एक सुरक्षित वातावरण में ही सम्भव हैं।

उन्होंने कहा, इस वर्ष माँ दुर्गा सुख और समृद्धि की पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। माँ जगज्जननी की कृपा सम्पूर्ण विश्व पर बनी रहे और चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो माँ भगवती से यही हमारी प्रार्थना है। मां अंबे की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। शक्ति स्वरूपा माता जगदंबा की अनुकंपा से सभी का जीवन सुख, शांति एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो। मां अम्बे सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, वैभव और यश प्रदान करें, मां जगदंबा की कृपा से संपूर्ण विश्व में सद्भावना का संचार हो और जगज्जननी की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो, आदिशक्ति माँ भगवती से यही कामना है। सुख, शांति और समृद्धि की मंगलमय कामनाओं के साथ जगज्जननी मां दुर्गा आदिशक्ति माँ भगवती के सभी रूपों की आराधना-उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि की सभी को परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं।

सफदरजंग अस्पताल में मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, के अवसर पर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ने दो सप्ताह की अवधि में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की। यह लगातार पाँचवाँ वर्ष है, और संस्थान की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार और प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना के नेतृत्व में रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का नेतृत्व किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 2024 के लिए यह थीम ₹रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार₹ है, साथ ही ₹सही करें, सुरक्षित बनाएं!₹ का नारा सभी पहलों के मूल में था। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की रोगी सुरक्षा समिति और गुणवत्ता प्रकोष्ठ ने 10 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले समारोहों की शुरुआत की, जहां अस्पताल भर के वार्डों और इकाइयों को रोगी सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने वाले पोस्टर और नोटिस बोर्ड से सजाया गया । पोस्टर, तस्वीरों और लघु वीडियो सहित इन रचनात्मक प्रयासों को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा एक साथ रखा गया था। प्रमुख कार्यक्रम रोगी सुरक्षा वॉकअराउंड था, जिसमें एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरा-संबद्ध छात्र शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान, चिकित्सा अधीक्षक और प्रिंसिपल ने नारंगी गुब्बारे छोड़े, जो रोगी देखभाल मानकों को बढ़ाने के लिए अस्पताल की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने कार्य केंद्रों पर रोगी सुरक्षा शपथ ली प्रयोगशाला रिपोर्टों में उच्च गुणवत्ता मानकों की निरंतर यात्रा की ओर, लैब तकनीशियनों के लिए एक व्यावहारिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने क्वालिटी सेल और आईएएमएम दिल्ली चैप्टर के सहयोग से तकनीशियनों के लिए ₹लैब की गुणवत्ता बढ़ाना: मेडिकल लैब में आईएसओ 15189:2022 मानकों को लागू करना₹ विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। समारोह का एक अन्य मुख्य आकर्षण अस्पताल भर के बहु-विषयक निवासियों के लिए नैदानिक केस प्रस्तुति प्रतियोगिता थी, जो 20 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी, और इसका विषय ₹रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार करना₹ था। केस प्रस्तुतियाँ अकादमिक रूप से उन्मुख होने के साथ-साथ जीवंत चर्चाओं से भरपूर थीं और विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा निर्णय लिया गया था। प्रतियोगिता में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अतिरिक्त डीडीजी और ईएमआर निदेशक डॉ. एल. स्वस्तिचरण, चिकित्सा अधीक्षक, वीएमएमसी के प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष और रोगी सुरक्षा समिति और गुणवत्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें संकाय, रेजिडेंट डॉक्टर, एमबीबीएस छात्र, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक स्टाफ शामिल थे। कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के सम्मान के साथ हुआ। इन आयोजनों ने रोगी सुरक्षा के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, और यह सुनिश्चित करने के अपने चल रहे मिशन पर जोर दिया कि प्रत्येक रोगी को सुना, मूल्यवान और सुरक्षित महसूस हो।

GDA से फ्लैट और प्लॉट खरीददारों के लिए अच्छी खबर, अगर करेंगे ऐसा तो कम जमा करना होगा किस्त का पैसा

जीडीए से भूखंड और फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। खासकर उनके लिए जो लगातार किस्त भरते हैं। अब वह आवंटी या खरीददार जो एक साथ पैसा जमा कराएंगे उनका मूलधन कम हो जाएगा। वीसी अतुल वत्स की तरफ से यह आदेश पारित किया गया। बता दें पहले किस्त के पैसे कम कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे।

गाजियाबाद। जीडीए से भूखंड और फ्लैट आवंटित कराने वाले आवंटियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो लगातार किस्त जमा कर रहे हैं। जीडीए की ओर ऐसे आवंटी जो एकमुश्त अधिक पैसा जमा कराएंगे। उन्हें नए तरीके से किस्त का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके लिए जीडीए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

एकमुश्त पैसा जमा करने से मूलधन होगा कम

जी हां, जीडीए (GDA) वीसी अतुल वत्स की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमे उन्होंने कहा कि यदि कोई एकमुश्त पैसे जमा करवाता है तो संबंधित बाबू केवल एकाउंट अनुभाग से वेरिफाई करवाने के बाद अपने स्तर ही किस्त को संशोधित करके आवंटी को जारी करेगा। एकमुश्त पैसा जमा करने से उसका मूलधन कम हो जाएगा। फिर पहले जमा कराई जा रही किस्त फिर उसे कम देनी होगी।

किस्त कम करवाने के लिए पहले लगाने पड़ते थे

इससे पहले कोई आवंटी बकाये रकम की एकमुश्त जमा कराता था तो उसे अपनी किस्त कम करवाने के लिए चक्कर लगाना पड़ेगा। आवंटी की फाइल को जीडीए का बाबू पहले अपर सचिव, सचिव और वीसी तक भेजता था। फिर उसका अप्रूवल आने के बाद किस्त कम की जाती थी।

इस पूरी प्रक्रिया में तीन से छह माह तक का समय लग जाता था, जिसमें आवंटी पैसा जमा कराने साथ ही जीडीए दफ्तर के चक्कर काटता था। इस आदेश से आवंटियों को राहत मिलेगी। आदेश के साथ वीसी ने चेतावनी भी दी है कि किसी प्रकरण में आवंटियों को परेशान किया गया तो संबंधित को तत्काल निलंबित किया जाएगा।

किस्त को कम किए जाने की एक के बाद कई फाइल सामने आई। तब पता चला कि वीसी के अप्रूवल के बाद ही किस्त को रिवाइज किया जाता है। तब उन्हें लगा कि बैंक में तो जैसे ही मूलधन में आवंटी एकमुश्त पैसा जमा करता है वैसे ही आटोमैटिक उसकी किस्त संशोधित होती है। इसमें एक शर्त यह है कि यदि आवंटी डिफाल्टर होगा तो जमा धनराशि को पहले देय किस्तों में से घटाया जाएगा।

अतुल वत्स, वीसी जीडीए

27 गांवों के सैकड़ों किसानों ने यीडा का किया घेराव
अब इस दिन निकलेगा छह फीसदी भूखंडों का ड्रा

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने सोमवार को 27 गांवों के सैकड़ों की तादाद में किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दिया। किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचे जिस कारण से सड़कों पर भारी जाम लग गया। यह धरना 100 दिनों से ज्यादा समय से चल रही है। यीडा के अधिकारी ने बताया कि छह प्रतिशत भूखंडों का ड्रा 27 सितंबर को निकाला जाएगा।

ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नेतृत्व में सोमवार को 27 गांवों के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। ट्रैक्टर-ट्रॉली से पहुंचे किसानों के कारण सड़क पर जाम लग गया।

जैतपुर गोलचक्कर के पास सभी किसान एकत्रित हुए, जहां से पैदल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पहुंचे। प्राधिकरण के बाहर 100 दिन से अधिक समय से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। किसानों को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में पुलिस मौजूद रही।

100 से अधिक समय से किसान धरने पर

भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र मुखिया ने बताया कि प्राधिकरण कार्यालय के सामने 100 से अधिक समय से किसान धरने पर बैठे हैं। प्राधिकरण की ओर से चर्चा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है।

किसान अपनी वाजिब मांग कर रहे हैं, बावजूद उसके सुनवाई नहीं हो रही। प्राधिकरण की नींद तोड़ने के लिए सोमवार को 27 गांवों के किसान एकत्रित हुए। इनमें काफी संख्या में महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल हुए। किसान अपने छह व चार प्रतिशत भूखंड की मांग कर रहें।

27 सितंबर को होगा छह प्रतिशत भूखंडों का ड्रा

आबादी भूखंडों को कई वर्ष पहले ही दे दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं का जा रही थी। धरना प्रदर्शन में किसानों से मिलने प्राधिकरण के ओएसडी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पाली और अजायबपुर गांव के छह प्रतिशत भूखंडों का ड्रा 27 सितंबर को किया जाएगा।

डाढ़ा व सिरसा गांव के किसानों की समस्या को 15 दिन में निस्तारित किया जाएगा। मौके पर नौ किसानों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड के कागज सौंपे गए। जानकारी दी चार प्रतिशत भूखंड के लिए शासन स्तर से जल्द कार्रवाई की जाएगी। छह प्रतिशत भूखंडों का निस्तारण हर महीने किया जाएगा।

इसके बाद किसान शांत हुए। धरने में भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगे राम त्यागी, मेरठ मंडल अध्यक्ष विनोद जटोली, जिला महासचिव चौधरी धनेश प्रधान, प्रदेश सचिव चौधरी दया प्रधान जिला प्रवक्ता विक्रम।

हरिंदर चौधरी, अनिल चौधरी, ललित भाटी, अमित भाटी, कपिल भाटी, बीरन, अनिल पाल, राजेंद्र आर्य, नरेंद्र, होते नागर, देवी राम पाल, रूपचंद, परवीन भाटी, सुनील भाटी, हरी बाबा, रघुराज, लाला प्रधान, जगदीश, सतीश आदि मौजूद रहे।

प्रॉपर्टी के चक्कर में 'हमसफर' बन गए 'अजनबी' प्लॉट बचाने के लिए अपना रहे ये हथकंडा

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि करोड़ों की संपत्ति के खातिर आठ दंपती ने अपने पवित्र रिश्ते को ही तोड़ दिया है। उन्होंने अपनी मर्जी से ही एक-दूसरे को तलाक दे दिया। वहीं यीडा की जांच में यह दिलचस्प बात सामने आई है। पढ़िए आखिर पूरा माजरा क्या है ?

ग्रेटर नोएडा। Zara Hatke Zara Bachke फिल्म में कपल (दंपती) लीगल सरकारी योजना के तहत फ्लैट का लाभ लेने के लिए नकली तलाक ले लेते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ऐसा हकीकत में देखने को मिला है।

YEIDA रिश्तों के आगे संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, लेकिन समय के साथ समाज में यह सोच अब बदल चुकी है। संपत्ति के लिए रिश्ते भी दिखावटी बन रहे हैं। यमुना प्राधिकरण में आठ दंपती ने अपने आवंटित भूखंडों को रद्द होने से बचाने के लिए पति-पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते की डोर को तोड़ दिया है, तलाक ले लिया है, ताकि पति-पत्नी दोनों के नाम आवंटित भूखंड को रद्द होने से बचाया जा सके।

प्राधिकरण 32 ऐसे औद्योगिक भूखंडों की जांच कर रहा है जो 10 परिवारों के सदस्यों में आवंटित हो गए हैं। इसके अलावा 16 भूखंड भी जांच के दायरे में हैं। एसीईओ की कमेटी इन भूखंडों के आवंटन की जांच कर रही है। सभी भूखंड चार हजार वर्गमीटर तक के हैं। इनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है।

प्राधिकरण के रडार पर हैं ऐसे आवंटन

यमुना प्राधिकरण Yamuna Authority अपनी योजना के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक ही भूखंड का आवंटन करता है। दंपती में एक को ही भूखंड आवंटन का नियम है, लेकिन प्राधिकरण की पूर्व में आईं औद्योगिक भूखंड योजना में 47 ऐसे प्रकरण हैं। जिसमें एक ही परिवार के लोगों को एक से अधिक भूखंडों का आवंटन हो गया है, या फिर जिस कंपनी के नाम पर भूखंड का आवंटन हुआ, उसमें वह शामिल हैं। ऐसे आवंटन प्राधिकरण के रडार पर हैं। प्राधिकरण के अपर कार्यपालक अधिकारी कपिल सिंह को इन आवंटन की जांच सौंपी गई है।

जांच में रोचक बात भी सामने आई है। पति-पत्नी दोनों के नाम भूखंड का आवंटन हो गया है तो नियमानुसार एक ही भूखंड उनके पास रह सकता है, लेकिन दंपती ने दोनों भूखंडों का आवंटन बचाने के लिए सहमति से तलाक ले लिया। ताकि अलग-अलग होने पर उन दोनों के नाम पर आवंटित भूखंड रद्द होने की संभावना समाप्त हो जाए।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि जांच में ऐसे 32 आवंटन सामने आए हैं, जिनका आवंटन 10 परिवार के सदस्यों के नाम पर हुआ है। इनके अलावा 16 आवंटन ऐसे मिले हैं, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य दोनों फर्म, दोनों कंपनी या एक फर्म एक कंपनी के पदाधिकारी हैं। एक आवंटी ने अपना भूखंड सरेंडर कर दिया है, लेकिन अन्य प्रकरणों की जांच जारी है। सभी आवंटित भूखंड सेक्टर 29 व 33 में हैं।

लाखों की भूखंडों की कीमत करोड़ों में

प्राधिकरण से आवंटित भूखंडों की करोड़ों में कीमत ने दंपती को तलाक तक पहुंचा दिया है। प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर सबसे कम होती है। जो भूखंड महज कुछ लाख रुपये में लोगों को मिले थे, आज उनकी कीमत करोड़ों में है। एक भूखंड का रद्द होने का मतलब करोड़ों रुपये हाथ से फिसलना है। इसलिए भूखंड को बचाने के लिए दंपती हर संभव हथकंडा अपना रहे हैं।

खरीदारों के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगा प्लॉट का मालिकाना हक

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है। अब सुपरटेक के अपकंट्री परियोजना में 608 खरीदारों को प्लॉट का मालिकाना हक मिल जाएगा। अब जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने इस मामले में जानकारी दी है। पढ़िए आखिर पूरा अपडेट क्या है।

ग्रेटर नोएडा। YEIDA Plot Scheme यूपी के ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के अपकंट्री परियोजना में 608 खरीदारों को प्लॉट का मालिकाना हक मिलेगा। यमुना प्राधिकरण ने प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है। खरीदारों को रजिस्ट्री के लिए 10345 वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा।

क्यों नहीं हो पा रही थी रजिस्ट्री

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 17 में सुपरटेक का अपकंट्री परियोजना है। बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। खरीदार रजिस्ट्री के लिए काफी समय से मांग कर रहे थे।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि पिछली बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री की मंजूरी का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

सुपरटेक के चेयरमैन ने कहा...

सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा का कहना है कि सौ एकड़ में विकसित परियोजना में विला, हाइराइज व प्लाट हैं। प्राधिकरण ने 608 प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति मांगी गई थी।

यह अनुमति मिलने के बाद जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खरीदार को रजिस्ट्री के लिए 10345 रुपये प्रति वर्गमीटर की दूर से भुगतान करना होगा।

'कांग्रेस चुनाव जीती तो नूंह छोड़ना होगा', मामन खान ने किसको दी चेतावनी?

कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मामन खान कहते सुनाई दे रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद नूंह के दंगों में उनके लोगों को परेशान करने वालों को देख लेंगे। साथ ही नूंह छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। पढ़िए पूरा मामला क्या है?

नूंह। 2024 जैसे -जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है तो नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह चुनाव जीतने के बाद नूंह के दंगों में उनके लोगों को परेशान करने वालों को देख लेने व नूंह छोड़ने की धमकी दे रहा है।

यह वीडियो फिरोजपुर झिरका विधानसभा के घाटा गांव की बताई गई। मामन खान लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे कि नूंह दंगे के दौरान उनके लोगों को तंग किया गया है। जिसके बारे में उन्हें तंग करने वाले व्यक्तियों के बारे में पूरे तौर पता है। ऐसे लोगों को चुनाव जीतकर सरकार आने पर निपटा दिया जाएगा।

धमकी भरे वीडियो की हर तरफ चर्चाएं

कांग्रेस प्रत्याशी के धमकी भरे वीडियो की चारों तरफ चर्चाएं हैं। भाजपा ने वीडियो का मामला प्रशासन के संज्ञान में भेज दिया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल का कहना है कि मामन खान हार सामने देख डर गया है। इसलिए माहौल फिर से खराब करने की कोशिश करके गलत ब्यानबाजी करने पर तुला हुआ है। ताकि क्षेत्र में माहौल को खराब किया जा सके। लेकिन इस बार जनता मामन खान के बहकावे में आने वाली नहीं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है।

माखन खान पर लगे थे दंगा भड़काने के आरोप

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ने मामन खान ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह तंग किए गए थे। विदित रहे कि मामन खान के विरुद्ध नूंह दंगा भड़काने के आरोप लगे थे। जिसमें उसके विरुद्ध चार प्राथमिकी दर्ज हैं

मानवता के तकाजे कब तक निभाएगा भारत

प्रताप सिंह पटियाल

बहरहाल कई देशों में आतंक व मजहबी उन्माद का शिकार होकर बेवतन हो रहे मजलूमों को शरण देकर भारत एक मुद्दत से मानवता के तकाजे निभा रहा है। लेकिन पड़ोसी मुल्कों पर चीन का दबदबा तथा विदेशी खूफिया एजेंसियों की बढ़ती पैठ से उत्पन्न माहौल भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती है'

प्राचीन काल से भारत अमन व इत्तेहाद का पक्षधर रहा है। इनसानियत की पैरवी करने वाली तहजीब, शांति, सद्भाव तथा शिष्टाचार भारतीय संस्कृति के मूल लक्षण हैं। 'जियो और जीने दो' अर्थात 'जीवन जीना अधिकार तथा समस्त प्राणियों को जीने देना कत्तव्य'। मान्यता है कि यह सिद्धांत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 'महावीर स्वामी' के उपदेशों का हिस्सा है, जो कि जंगी जुनून में मदहोश होकर विश्व को तीसरी आलमी जंग के मुहाने पर ले जा रहे देशों तथा दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले मुल्कों के लिए एक प्रकाशमान दर्शन है। मौजूदा दौर में मजहबी कट्टरवाद तथा आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे वैश्विक स्तर पर एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब युद्ध, मजहबी उत्पीडन व आतंकवाद जैसी भीषण आपदाओं के कारण अपना मुल्क छोडने वाले बेगुनाह लोगों के लिए भारत ने हमेशा मसीहा की भूमिका निभाई है। यहां तक कि हिंदोस्तान से गद्दारी करने वाले लोगों के प्रति भी भारत का नजरिया नैतिकता का ही रहा है। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 'जोगिंद्रनाथ मंडल' अविभाजित हिंदोस्तान के दौर में मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उन मोहतरम ने भारत के विभाजन में अपना शिद्दत भरा किरदार अदा किया था। बटवारे के दौर में जोगिंद्रनाथ मंडल ने जातिवाद की पुरजोर पैरवी करके असम राज्य के सिलहट क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। नतीजतन सिलहट अब बांग्लादेश में मौजूद है।

विभाजन के बाद जोगिंद्रनाथ मंडल दलित व पिछड़े वर्ग का रहनुमां बनकर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान के गर्वनर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगिंद्रनाथ मंडल को पाक हुकूमत की काबीना में 'कानून व श्रम' मंत्री नियुक्त कर दिया। मगर वजूद में आते ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर मजहब के नाम पर तशद्दुद का दौर शुरू हो गया था। कत्लोगारत के उस खौफनाक मंजर से जब पाकिस्तान का धर्मनिरपेक्ष चेहरा बेनकाब हुआ, तो पाक में भाईचारे के पैरोकार बनकर गए जोगिंद्रनाथ मंडल ने पाक वजीरे आजम 'लियाकत अली' को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पाकिस्तान के मजहबी जुनून के आगे बेबस होकर जोगिंद्रनाथ मंडल को दोबारा भारतभूमि पर ही शरण लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही जिन्ना को अपने मुल्क के लिए 'कौमी तराना' की जरूरत महसूस हो चुकी थी। उस वक्त जिन्ना ने उर्दू सहाफत के नामवर शायर 'जगन्नाथ आजाद' से पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने की गुजारिश की। जगन्नाथ आजाद द्वारा लिखा गया पाकिस्तान का कौमी तराना 14 अगस्त 1947 की रात को रेडियो 'लाहौर' से पहली बार नसर हुआ था। लेकिन सितंबर 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद जगन्नाथ आजाद द्वारा लिखे गए पाक कौमी तराने पर मजहबी गर्दिश का साया पड़ गया। पाकिस्तान के मजहबी रहनुमाओं को एक गैर इस्लामी शायर का लिखा कौमी तराना रास नहीं आया। नतीजतन जिन्ना का मुस्तहब पाक कौमी तराना बदल दिया गया। मजहबी हिकारत से आहत होकर जगन्नाथ आजाद ने अपने

पूर्वजों की पुश्तैनी विरासत को अपनी जन्मभूमि मियांवली में त्याग कर पाकिस्तान को अलविदा कह कर भारत में ही शरण ली थी। अंग्रेज वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा सन-1905 में बंगाल विभाजन की अजीयत भरी कारकर्दगी से मायूस होकर 'रविंद्रनाथ टैगोर' ने बंगाल में इत्तेहाद का माहौल बरकरार रखने के लिए 'आमार सोनार बांग्ला' नामक गीत की रचना की थी। उस दौर में 'बंगदर्शन' नामक पत्रिका में प्रकाशित वो नगमा काफी लोकप्रिय हुआ था।

भारत के रहमो करम से सन-1971 में वजूद में आए बांग्लादेश ने अपनी 'यौम-ए-तासीस' के वक्त टैगोर के उस नगमें को अपना कौमी तराना तस्लीम कर लिया था, लेकिन 'आमार सोनार बांग्ला' सन-1975 में ही मजहबी कट्टरपंथ का शिकार हो गया। बांग्लादेश की मजहबी जमातों के आगे बेबस होकर राष्ट्रपति 'मुश्ताक अहमद' द्वारा गठित की गई कमेटी के मजहबी रहनुमां काजी नसरूल इस्लाम ने टैगोर के लिखे तराने को रुखसत करने का मश्विरा पेश कर दिया था। बांग्लादेश की मौजूदा मजहबी जमातें भी उसी तहरीर को दोहरा रही हैं। अपने चर्चित उपन्यास 'लज्जा' के जरिए बांग्लादेश के मजहबी कट्टरपंथ को बेनकाब करने वाली लेखिका 'तस्लीमा नसरीन' को सन-1994 में अपना मुल्क बांग्लादेश छोडना पड़ा। वहां की कट्टरपंथी जमातों तथा कई आतंकी संगठनों ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया था। तस्लीमा नसरीन ने सन-2004 से भारत में शरण ली है। बांग्लादेश में हिंसक कारवाईयों से हालात इस कदर बेकाबू हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों लोग भारत में शरण लेने को आमादा हैं। 1980 के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण हजारों तमिल शरणार्थियों को भारत के दक्षिणी राज्यों में पनाह दी गई। अफगानिस्तान पर सन-1979 में सोवियत आक्रमण तथा तालिबान की हुकूमत के दौर में अस्थिरता का माहौल पैदा होने से हजारों अफगान नागरिक भी भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। नेपाल, तिब्बत व भूटान जैसे देशों की एक बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। दूसरे मुल्कों की स्वतंत्रता को कायम रखने व अकलियतों के हकूक की आवाज भारत हमेशा बुलंद करता है।

मजहब की रहनुमाई करने वाले कई देश हैं, लेकिन जातिवाद व मजहबी हिकारत के कारण बेघर हो रहे लोगों को शरण देने की जहमत कोई भी मुल्क नहीं उठाता। बहरहाल कई देशों में आतंक व मजहबी उन्माद का शिकार होकर बेवतन हो रहे मजलूमों को शरण देकर भारत एक मुद्दत से मानवता के तकाजे निभा रहा है। लेकिन पड़ोसी मुल्कों पर चीन का दबदबा तथा विदेशी खूफिया एजेंसियों की बढ़ती पैठ से उत्पन्न माहौल भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती है। अतः एटमी कूवत से लैस व विश्व की चौथी ताकतवर सैन्यशक्ति की हैसियत रखने वाले भारत को अपनी सैन्य ताकत का पैगाम भी देना होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने यूरोपीय बाजारों को ई-मोटरसाइकिल का शुरू किया निर्यात

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव ने मंगलवार, 24 सितंबर को अपनी ई-मोटरसाइकिल एफ77 मैक 2 का निर्यात शुरू किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने यूरोपीय संघ (ईयू) के बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।

कुमारस्वामी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "यूरोपीय बाजार में अल्ट्रावॉयलेट का विस्तार भारत के मोटर वाहन उद्योग के लिए एक निर्णायक क्षण है, जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की हमारे देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है।"

कुमारस्वामी और कंपनी के अधिकारियों के अलावा कर्नाटक के उद्योग और वाणिज्य मंत्री एम बी पाटिल भी बेंगलुरु में कंपनी के विनिर्माण संयंत्र में आयोजित उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह (निर्यात की शुरुआत) इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारतीय स्टार्टअप इलेक्ट्रिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवोन्मेषण को आगे बढ़ा रहे हैं। यह निर्यात पहल भारत को वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र बनाने के हमारी सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।"

अल्ट्रावॉयलेट के सह-संस्थापक नीरज राजमोहन ने कहा कि यूरोप में कंपनी का प्रवेश वैश्विक बाजारों के लिए भारत में डिजायन इलेक्ट्रिक वाहनों को वितरित करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कंपनी ने बयान में कहा कि भारत में निर्मित, उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के निर्यात से वैश्विक ईवी उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

जेएसडब्ल्यू समूह ने 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना को किया ओडिशा से महाराष्ट्र स्थानांतरित

परिवहन विशेष न्यूज

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जेएसडब्ल्यू समूह ने नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली बीजू जनता दल सरकार के साथ समझौते को औपचारिक रूप देने के सात महीने बाद, अपनी 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी परियोजना को ओडिशा से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का फैसला किया है।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाला यह समूह अब अपनी ईवी और संबंधित परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नागपुर पर विचार कर रही है।

इस साल फरवरी में जेएसडब्ल्यू समूह ने कटक और पारादीप में ईवी और बैटरी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नियोजित विनिर्माण कार्यों में इलेक्ट्रिक वाहन, 50 GWh बैटरी प्लांट, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, लिथियम रिफाइनरी और विभिन्न संबंधित उत्पादन इकाइयाँ शामिल थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएसडब्ल्यू अपने ईवी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक चीनी सेल प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों की भी संभावना तलाश रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपनी ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, खासकर तब जब जेएसडब्ल्यू स्टील, जो इसकी मुख्य सहायक कंपनी है, पहले से ही एमजी मोटर इंडिया के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्टील की आपूर्ति कर रही है।

इसके अतिरिक्त, जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय बाजार में ऑटोमेकर की उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से एमजी मोटर इंडिया के साथ अपने सहयोग का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उल्लेखनीय विकास बैटरी रेंटल मॉडल का शुभारंभ है, जो ग्राहकों को अपने एमजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी किराए पर लेने की अनुमति देगा, जिससे शुरुआती लागत कम हो जाएगी और ईवी स्वामित्व अधिक सुलभ हो जाएगा।

इसके अलावा, जेएसडब्ल्यू और एमजी मोटर इंडिया एमजी जेएसडब्ल्यू सेलेक्ट नाम से एक प्रीमियम बिक्री नेटवर्क शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो एमजी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष बिक्री, सेवा और सहायता प्रदान करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डीलरशिप मॉडल SAIC मोटर्स के वैश्विक पोर्टफोलियो से उच्च श्रेणी के वाहनों की एक नई श्रृंखला के लिए एक सहज और उच्चस्तरीय स्वामित्व अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

गुजरात और महाराष्ट्र वर्तमान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने की होड़ में हैं। अगस्त में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें नागपुर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी PSP इलेवन लिमिटेड द्वारा 25,000 करोड़ रुपये की लिथियम बैटरी पहल शामिल है, जिससे 5,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड छत्रपति संभाजी नगर (पूर्व में औरंगाबाद) में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए राज्य का पहला बड़े पैमाने का कारखाना स्थापित करने के लिए 27,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य सालाना 500,000 इलेक्ट्रिक यात्री कारों और 100,000 वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करना है, जिससे 5,200 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

ओडिशा से 40,000 करोड़ रुपये की ईवी परियोजना वापस लेने की कोई योजना नहीं: जेएसडब्ल्यू समूह

परिवहन विशेष न्यूज

जेएसडब्ल्यू समूह ओडिशा से अपनी प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी परियोजना को वापस नहीं ले रहा है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार, 24 सितंबर को यह जानकारी दी।

कंपनी का यह बयान मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि जेएसडब्ल्यू समूह अपनी ईवी तथा बैटरी परियोजना को पूर्वी राज्य से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।

इन मीडिया खबरों के बारे में पूछे जाने पर चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कार्यालय के कार्यकारी उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट रणनीति) रंजन नायक ने कहा, '' हम ओडिशा से परियोजना वापस नहीं ले रहे हैं।''

जेएसडब्ल्यू समूह ने शनिवार, 10 फरवरी, 2024 को राज्य में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी बैटरी विनिर्माण परियोजना की स्थापना के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

कटक जिले में जेएसडब्ल्यू समूह ने ईवी वाहन तथा कलपुर्जा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी, जबकि जगतसिंहपुर जिले में उसने तांबा स्मेल्टर संयंत्र तथा लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

कंपनी के अपनी परियोजना को महाराष्ट्र में स्थानांतरित की खबरों के बीच ओडिशा के उद्योग मंत्री संपद स्वैन ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार ईवी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जेएसडब्ल्यू समूह से बात कर रही है।

स्वैन ने कहा था कि ''मीडिया में आ रही खबरों'' में कंपनी की योजनाओं के बारे में जो दावा किया गया है उसकी राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

निसान मेगनाइट फेसलिफ्ट का नया टीजर सोशल मीडिया पर हुआ जारी

जापानी वाहन निर्माता Nissan की ओर से भारतीय बाजार में दो एसयूवी ऑफर की जाती हैं। लेकिन इनमें से बजट एसयूवी के तौर पर आने वाली Nissan Magnite के Facelift वर्जन को जल्द लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर नया टीजर जारी किया है। इसमें क्या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। वाहन निर्माता Nissan की ओर से भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट में दो गाड़ियों की बिक्री की जाती है। जिनमें से एक एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट और दूसरी फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में लाई जाती है। अक्टूबर में कंपनी नई गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एंट्री लेवल Nissan Magnite Facelift के लॉन्च से पहले नया टीजर जारी किया गया है। इसमें क्या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जारी हुआ नया टीजर

कंपनी की ओर से Nissan Magnite Facelift को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले सोशल मीडिया पर इसका नया टीजर जारी किया गया है। 11 सेकेंड के नए टीजर में इसके टायर को दिखाया गया है। इसके साथ ही गाड़ी के नए लुक की जानकारी भी मिल रही है।

रिपोर्ट्स से मिली जानकारी

कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा एसयूवी Nissan Magnite के फेसलिफ्ट वर्जन में ज्यादातर कॉस्मैटिक बदलाव ही किए जाएंगे। इसके इंजन में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद कम है।

क्या होंगे बदलाव

जानकारी के मुताबिक इसके इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना कम है। इसके फ्रंट बंपर, हेडलाइट्स के साथ ही ग्रिल में बदलाव किया जाएगा और रियर में भी बंपर और टेल लाइट्स और अलॉय व्हील्स में बदलाव करने के बाद इसे नयापन देने की कोशिश की जा सकती है। इंटीरियर में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

कितनी होगी कीमत

मौजूदा मैग्नाइट को निसान की ओर से 5.99 लाख रुपये से लेकर 11.27 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के बीच ऑफर किया जाता है। लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन की एक्स शोरूम कीमत में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला Tata Punch, Renault Kiger, Maruti Fronx, Citroen Basalt, Toyota Taisor और Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी से होता है।

दिल्ली में अक्टूबर में ई-वाहन परेड का किया जाएगा आयोजन ताकि इसके उपयोग के साथ-साथ बिक्री को दिया जा सके

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में अक्टूबर में ई-वाहन परेड का किया जाएगा आयोजन ताकि इसके उपयोग के साथ-साथ बिक्री को दिया जा सके बढ़ावा

दिल्ली का पर्यावरण विभाग अक्टूबर की शुरुआत में राजघाट पर 'ई-वाहन परेड' का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

अधिकारियों का अनुमान है कि इस कार्यक्रम में 500 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन भाग लेंगे और इच्छुक वाहन मालिकों के लिए पंजीकरण लिंक की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस आयोजन के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं, जिसकी लागत करीब 5.76 लाख रुपये आने की उम्मीद है। निविदाएं 30 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी और निविदा प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर परेड आयोजित की जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया, ₹इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को परेड में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।₹

अधिकारी ने कहा, ₹इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।" हाल ही में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद कार्यभार संभालने वाले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जोर देकर कहा कि आने वाले महीनों में सरकार का ध्यान वायु प्रदूषण से निपटने पर रहेगा।

गोपाल राय ने कहा, ₹सर्दियों के दौरान सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए हम पहले ही 33 विभागों के साथ बैठक कर चुके हैं।"

उन्होंने कहा, ₹आगे के सुझावों पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव से मिलूंगा। शीतकालीन कार्य योजना तैयार है और विधानसभा सत्र के कारण इसे 27 के बजाय 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।"

गोपाल राय ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सहयोगी प्रयासों से पूरे वर्ष दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया जा सकता है और उनका लक्ष्य सर्दियों के महीनों में भी इसी तरह के परिणाम हासिल करना है।

अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने एक ईवी नीति पेश की, जो ईवी खरीदारों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और 2024 तक राजधानी में पंजीकृत हर चार नए वाहनों में से एक को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है।

माईटीवीएस ने पेश किया मोबिलिटी-ऐज-ए-सर्विस

परिवहन विशेष न्यूज

देश के सबसे बड़े डिजिटल ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट प्लेटफॉर्म माईटीवीएस ने अंतिम छोर तक सेवा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े के परिचालकों के लिए देशव्यापी 'मोबिलिटी-ऐज-ए-सर्विस' (मास) प्लेटफॉर्म पेश करने का ऐलान किया। यह प्लेटफॉर्म तीन अरब डॉलर के टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का हिस्सा है।

अपने खुद के वाहन रखने के बजाय वाहन बेड़े के परिचालक, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियां अब माईटीवीएस की सेवाओं का फायदा उठा सकेंगी। प्लेटफॉर्म के तहत संपूर्ण ईवी बेड़े के जीवन चक्र के लिए एक ही जगह सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) समेत पूरे तंत्र के भागीदारों को इससे जोड़ा गया है।

यह प्लेटफॉर्म पट्टे से लेकर रियल-टाइम बेड़ा प्रबंधन, सेवा, पुर्जा प्रबंधन (1.8 लाख एसकेयू के डिजिटल कैटलॉग के साथ), चार्जिंग समाधान (पोर्टेबल चार्जर और माईटीवीएस चार्जिंग स्टेशन सहित), टेलीमैटिक्स, रोडसाइड सहायता, बीमा और टायर प्रबंधन तक बेड़े का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करता है। बेड़े की आयु और दक्षता बढ़ाने के लिए वाहन नवीनीकरण सेवाएं भी इससे मिल सकेंगी।

कंपनी के अनुसार माईटीवीएस अपने 'मास' प्लेटफॉर्म के जरिये अंतिम छोर के परिचालकों का पसंदीदा ब्रांड बन जाएगा और उन्हें अपने ग्राहकों के साथ तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। यह एंड-टू-एंड सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसने सभी हितधारकों के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया है और वह क्विक कॉमर्स क्षेत्र के भागीदारों को डिजिटल रूप से जरूरत के अनुरूप समाधान प्रदान करेगा। शुरुआत के तहत माईटीवीएस ने भारत में ईवी आधारित प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी मोइवींग के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

माईटीवीएस का यह कदम कंपनी की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा, जो व्यक्तिगत आवागमन से लेकर आवाजाही के बेड़े वाले समाधानों में की दिशा में बढ़ रही है। भारत में क्विक कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी है और इसे कारोबारी कंपनियों के टिकाऊ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिफाइड करने की जरूरत होगी। माईटीवीएस का 'मास' प्लेटफॉर्म वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी लाने के लिए प्लग-ऐंड-प्ले समाधान देगा और साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में भी सक्षम बनाएगा। यह पहल सरकार के तेजी से ईवी अपनाने और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन करेगी।

माईटीवीएस के प्रबंध निदेशक जी श्रीनिवास राघवन ने कहा, 'मास प्लेटफॉर्म को व्यक्तिगत आवागमन और मोबिलिटी बेड़े वाले ग्राहकों, दोनों की ही उभरती जरूरतों को पूरा करने, दक्षता प्रदान करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्विक कॉमर्स कंपनियां लागत को सुव्यवस्थित करने और अपने टिकाऊ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े तलाश रही हैं।'

कायम रहे 'नीट युजी' की व्यवस्था

विजय गर्ग

अधिकांश छात्र का यह सपना होता है कि स्कूली शिक्षा के बाद वह डाक्टर या इंजीनियर बने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका स्वप्न होता है। कि आइएएस या अन्य सरकारी सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यह भी सही है कि सभी लोग ये परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाते, लेकिन यदि व्यवस्था में ईमानदारी हो तो कुछ सक्षम विद्यार्थी अवश्य ऐसा कर पाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसी भी आवाज उठने लगी है कि नीट की परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह मांग परीक्षार्थियों की और से नहीं, बल्कि कुछ राजनेताओं की और से उठ रही है।

अब सवाल यह है कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की व्यवस्था को भंग कर दिया जाता है तो उसके स्थान पर कौन से व्यवस्था लागू होगी? इसमें यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि नीट की व्यवस्था लागू होने से पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं कैसे होती थीं, और उसके क्या गुण दोष थे? नीट की परीक्षा लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यदि नीट के स्थान पर पुनः पुरानी व्यवस्था लागू होती है तो उसका मेडिकल कालेजों में उम्मीदवारों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? पेपर लीक की घटना को आधार बनाकर नीट व्यवस्था को भंग करना कितना उचित होगा, इस पर विचार करना जरूरी है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा का इतिहास

नीट लागू होने से पहले अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) द्वारा परीक्ष आयोजित की जाती थी जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मेडिकल एवं डेंटल कालेजों के एमबीबीएस एवं बीडीएस डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु कम से कम 15 प्रतिशत सीटें इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती थी। यह सही है कि कुछ बेईमान तत्वों के कारण नीट और यूपीएससी परीक्षाओं में कुछ स्थानों पर पेपर लीक होने के कारण विद्यार्थियों को धक्का लगा है। वैसे निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया हमेशा ही विवाद का विषय रही है। नीट से पहले प्राइवेट मेडिकल संस्थान प्रवेश परीक्षा आयोजित तो करते थे, लेकिन उनमें अधिकांश नामांकन कालेजों को दी जाने वाली राशि के आधार पर होता था। कुछ अपवाद को छोड़ मोटी फीस के

अलावा भारी नकद रकम अलग से चुका कर प्राइवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिलता था, तो ऐसे में यह व्यवस्था मेडिकल की पढ़ाई में असमानता का एक बड़ा कारण हुआ करती थी। ऐसे में हालांकि वर्ष 2012 में सरकार द्वारा अलग-अलग प्रांतों और कालेजों के आधार पर विविध प्रकार की परीक्षाओं से निजात पाने के लिए देश में एक साझी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया, जिसके खिलाफ प्राइवेट कालेजों के प्रबंधन ने अदालत में आपत्ति दर्ज की। इस मुकदमे में न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रबंधन के हित में फैसला देते हुए साझी परीक्षा को यह कहकर निरस्त कर दिया कि यह प्राइवेट कालेजों के अधिकारों का उल्लंघन है।

नई व्यवस्था

केंद्र में नरेन्द्र मोद सरकार आने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2013 के उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन किया। पांच जजों की बेंच ने निर्णय को पलटते हुए 'नीट' परीक्षा को संवैधानिक ठहराते हुए साझी परीक्षा का रास्ता साफ किया। यह अनुभव किया गया कि 'नीट' की सझी परीक्षा के बाद सरकारी कालेजों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कालेजों में भी योग्यता के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश हो पा रहा है। लेकिन जबसे 'नेट' की परीक्षा शुरू हुई है, मेडिकल कालेजों में भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई का स्रोत बंद हो चुका है। कुछ समय पहले 'नीट' की परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना प्रकाश में आई तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने नोट परीक्षा समाप्त करने की मांग करनी शुरू कर दें हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में जितने भी मेडिकल या डेंटल कालेज हैं, उनमें एक बड़ी संख्या राजनेताओं द्वारा स्थापित संस्थानों की है ऐसे में प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रबंधक नीट की परीक्षा समाप्त कर मेडिकल प्रवेश को उसी पूराने ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं, जहां उन्हें मनमाने तरीके से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर भारी रकम कमाने का मौका मिल सके। पेपर लीक की कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर इन निहित स्वार्थ वाले लोगों के बहकावे में आकर नीट की परीक्षा को समाप्त करना हमें फिर से उसी अंधे कुएं में धकेल देगा और मेडिकल में प्रवेश फिर से पैसे वाले लोगों का खेल बनकर रह जाएगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट-152107

शतरंज के 'राजा-रानी'

शतरंज का जिक्र होते ही महान कथाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद की याद ताजा होने लगती है। उनकी प्रख्यात कहानियों में 'शतरंज के खिलाड़ी' भी एक थी, जिस पर फिल्म भी बनाई गई। वह शतरंज वक्तकटी का जरिया थी, लेकिन आज यह पेशेवर खेल है, जो दुनिया भर में खेला जाता है। भारत ने इसी खेल के ओलिंपियाड में नया और स्वर्णिम इतिहास रच दिया। दोहरा स्वर्णिम कीर्तिमान भी स्थापित किया। 1927 में 'चेस ओलिंपियाड' का अधिकृत और वैश्विक सफरनामा शुरू हुआ था। अब 2024 में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने सर्वश्रेष्ठ रहते हुए, पहली बार, दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इन मुकाबलों में रूस, चीन, अमरीका, उजबेकिस्तान सरीखे चैम्पियन देश पिछड़ गए और भारतीय खिलाडियों ने सुनहरी इबारत लिख दी। कुल 195 देशों की 197 टीमों और महिलाओं में 181 देशों की टीमों में भारत 'सर्वश्रेष्ठ' रहा। वाह! कमाल है!! इस अभूतपूर्व खेल उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। युवा खिलाडियों ने खेल के साथ-साथ देश का सम्मान भी आसमान तक पहुंचा दिया। अकल्पनीय, अतुलनीय तो यह रहा कि पुरुष टीम और उसके चैम्पियन खिलाड़ी डी. गुकेश 'अजेय' रहे। उन्होंने अधिकतर गेम जीते और एक-दो गेम ड्रा खेलने पड़े। पुरुषों में गुकेश और अर्जुन एरिगैसी, महिलाओं में दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने 'व्यक्तिगत स्वर्ण पदक' भी हासिल किए। भारत में पेशेवर शतरंज खेलना अपेक्षाकृत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी 2014, 2022 में चेस ओलिंपियाड के कांस्य पदक विजेता बनते रहे हैं। चुनौती के स्पष्ट संकेत थे कि भारत एक दिन 'सर्वोच्च' भी हो सकता है। हालांकि तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद पांच बार शतरंज के 'विश्व चैम्पियन' बने और खेल के महानतम खिलाडियों की जमात में शामिल हुए। उनकी विरासत आज गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञाननंदा, विदित गुजराती सरीखे युवा खिलाडियों में झलकती है। महिलाओं में भी शतरंज की एक सशक्त, विजेता पीढ़ी दिव्या, हरिका, वैशाली, वंतिका, तानिया सचदेव और दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी आदि के रूप में सामने है। इन तमाम खिलाडियों को वल्ड रैंकिंग हासिल है। गुकेश विश्व चैम्पियनशिप के 'चैलेंजर' हैं। वह नवम्बर, 2024 में सिंगापुर में मौजूदा विश्व चैम्पियन डिंग लिरेन से मुकाबला करेंगे। गुकेश अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जीत कर ऐसी स्थिति में आए हैं कि वह विश्व चैम्पियन को चुनौती दे पा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मात्र 18 वर्षीय किशोर गुकेश अगला विश्व चैम्पियन बनकर दुनिया के सामने आए।

छात्र विकास, नेतृत्व के लिए आवश्यक रणनीतियाँ : विजय गर्ग

सार्वजनिक रूप से बोलने से छात्रों का विकास और नेतृत्व बढ़ता है, लेकिन ग्लोसोफोबिया अक्सर उनकी क्षमता में बाधा डालता है। चूँकि 77% व्यक्ति इस डर का सामना कर रहे हैं, शैक्षिक सेटिंग में इससे निपटना उनकी उन्नति के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक रूप से बोलना सबसे प्रभावी कौशलों में से एक है जो प्रस्तुतियों से लेकर छात्रों के व्यक्तिगत विकास और उनके नेतृत्व गुणों के निर्माण तक विभिन्न गतिविधियों में सहायक हो सकता है। हालाँकि, दर्शकों के सामने बोलने का विचार बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से, ग्लोसोफोबिया या सार्वजनिक रूप से बोलने की चिंता छात्रों के बीच एक लगातार समस्या है, जिसके कारण टालमटोल होता है और विभिन्न अवसर छूट जाते हैं। पी सार्वजनिक रूप से बोलना एक प्रकार का सामाजिक भय है, जिसे दूसरों के सामने बोलने का डर या चिंता के रूप में वर्णित किया गया है। साइकसेंट्रल इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट हो सकती है; शारीरिक रूप से, इसमें पसीना आना, कांपना और दिल की धड़कन का बढ़ना शामिल है। साथ ही, बाद वाला शर्मिंदगी या नकारात्मक निर्णय का डर है। अनुसंधान से पता चलता है कि यह समस्या छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रयासों में प्रभावित करती है। फ्रंटियर्स इन कम्युनिकेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जब सार्वजनिक रूप से बोलने की बात आती है तो लगभग 77% लोगों को किसी न किसी प्रकार की चिंता होती है। यह उच्च प्रतिशत इस समस्या से निपटने की आवश्यकता को दर्शाता है, विशेषकर शिक्षण संस्थानों में जहां सार्वजनिक बोलना एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सॉफ्ट-स्किल ट्रेनर शालिनी अग्रवाल ने छात्रों के बीच सार्वजनिक रूप से बोलने की चिंता पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा किए हैं गौरतलब है कि तैयारी काफी हद तक चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी सामग्री पहले से ही व्यवस्थित कर लें ताकि उनके पास अध्ययन के लिए पर्याप्त समय हो। इसमें विषय के लिए प्रारंभिक खोज करना और ग्राफिक प्रस्तुति की रूपरेखा और संगठन बनाना शामिल है। अकेले और कुछ लोगों के

सामने भाषण का अभ्यास करने से भाषण देने में आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। संदेश पर ध्यान दें, दर्शकों पर नहीं श्रोता की ओर से संदेश पर जोर बदलने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। छात्रों को उनके द्वारा पैदा की गई धारणा के बजाय दिए जा रहे संदेश और उसके लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फोकस में यह बदलाव आत्म-चेतना को कम करने और वितरण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकें चिंता को प्रबंधित करने के लिए विज़ुअलाइज़ेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। छात्र सफलतापूर्वक अपना भाषण देते हुए, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए कल्पना कर सकते हैं। यह सकारात्मक प्रेरक भाषण आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और डर को कम कर सकता है। साँस लेने योग्य उपलब्धियाँ साँस लेने के व्यायाम चिंता के शारीरिक लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को अपनी नसों को शांत करने के लिए भाषण से पहले और भाषण के दौरान धीमी, गहरी सांसें लेना सिखाएं। नियंत्रित श्वास हृदय गति को कम कर सकती है और शांति की भावना पैदा कर सकती है। क्रमिक अनुभव ए ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने के संपर्क में आते हैं, उनका डर कम हो जाता है या दूसरे शब्दों में, छात्र 'असंवेदनशील' हो जाते हैं। छोटे-छोटे बोलने के कार्यों से धीरे-धीरे आगे बढ़ें, जैसे किसी छोटे समूह के सामने बोलना या कक्षा चर्चा में योगदान देना। जैसे-जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है दर्शकों और प्रस्तुतियों का आकार और कठिनाई धीरे-धीरे बढ़ाई जानी चाहिए। सकारात्मक आत्म-बातचीत विद्यार्थियों को नकारात्मक विचारों का सकारात्मक कथनों से मुकाबला करना सिखाएं। कहने के बजाय, ₹मैं असफल हो जाऊंगा, ₹ वे कह सकते हैं, ₹मैं अच्छी तरह से तैयार हूं और अच्छा भाषण देने में सक्षम हूं।" सकारात्मक आत्म-चर्चा आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद कर सकती है। इस प्रकार, छात्र उपर्युक्त व्यावहारिक रणनीतियों के उपयोग के माध्यम से डर को आत्मविश्वास में बदलने में सक्षम हैं। सार्वजनिक बोलना न केवल एक संपत्ति है, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में एक उपकरण भी है जो इसे विकसित करना चाहता है। एक बार जब छात्र अपनी चिंता पर काबू पा लेते हैं, तो वे नए दरवाजे खोलने में सक्षम होंगे और सर्वश्रेष्ठ बन सकेंगे।

एक गौसेवक से मुलाकात

विजय गर्ग

भारत में एक नई संकल्पना उभरती है। आज भारत में स्त्री जागरण पूरी तरह पश्चिम के नारीवाद से प्रभावित नजर आता है, जबकि भारत और पश्चिम के जनमानस में भारी अंतर है। जब हम भारत में नारी सशक्तीकरण के पश्चिमी मॉडल की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी सुधारों का अभाव दिखता है। भारत का वर्तमान स्त्री विमर्श शहरी मध्यम वर्गीय और अभिजात्य वर्ग तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न आय वर्ग में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और शोषण की समस्या आम है। वे अभी इनको लेकर मुखर भी नहीं हैं और सहती रहती हैं। शहरों और उच्च वर्ग में इस तरह की घटनाओं को लेकर महिलाएं रिपोर्ट कर रही हैं।

भारतीय जनमानस में एकाएक महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार्य होना आसान नहीं है। पिता, भाई और पति के संरक्षण में पलने, बढ़ने के बाद उनके अधिकारों से परे जाने में अभी वे सक्षम नहीं हुई हैं, जबकि यूरोपीय देशों के नारी सशक्तीकरण का मॉडल एक अलग दृष्टि को दर्शाता है। भारतीय समाज अब भी स्त्रियों को मान्य रूप से बराबरी का दर्जा नहीं दे पाया है। बड़ा वर्ग अब भी स्त्री को अबला और भोग का माध्यम ही मानता है। स्त्री उत्थान के विमर्श के लिए यह समझना जरूरी है कि हर समाज की अपनी वैचारिक विशेषता, संस्कृति और सीमाएं होती हैं। नारी सशक्तीकरण के लिए जो भी नियम, कानून बने हैं, वे सब पश्चिम से प्रभावित हैं। ऐसे में भारतीय दलित स्त्री की वैचारिकी क्या हो सकती है। इसकी संकल्पना भारतीय नारी ही कर सकती है। भारत की नई स्त्री वह होगी, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और स्वतंत्र विचारों के अधिकार से अच्छी तरह वाकिफ हो।। जल संरक्षण के मुद्दे पर अब जागरूकता से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। हमारे पुरखे जल आपूर्ति के लिए जल विभाग या जल मंत्रालयों पर निर्भर नहीं थे।

पूर्वजों द्वारा पेयजल संग्रहण की सदियों पुरानी उत्तम पद्धति बावड़ियां और कुएं आज भी मौजूद हैं। इन पारंपरिक जल स्रोतों के गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल का आज भी कोई विकल्प नहीं है। इनके जरिये हर गांव में जलतंत्र विकसित करके पूर्वजों ने अनूठी मिसाल कायम की थी। इन्सानों के अलावा जीव-जंतु और पशु-पक्षी की प्यास भी इन्हीं जल संसाधनों पर आकर मिटती थी। ग्रामीण संस्कृति से गहरा नाता रखने वाले पारंपरिक जल स्रोतों की कृषि अर्थ तंत्र को समृद्ध करने में भी मुख्य भूमिका रही है। कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी जलाशयों के तटों पर होता आया है। मगर विडंबना है कि आज खनन माफिया, उद्योगों और आग उगल रही फैक्टरियों से उत्पन्न जहरनुमा प्रदूषण से नदियों तथा प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी दूषित हो चुका है। सरकारी हैंडपंप और पेयजल परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। इसलिए जल प्रबंधन की परिपाटी के उच्च स्तर, धार्मिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व को समेटे इन जल स्रोतों का अस्तित्व बचाना होगा। इसके लिए हमें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारें जल बचाने के लिए कोई पहल करती हैं तो हमें उसमें सहभागित करने की जरूरत है। यह हमारी व्यक्तिगत जरूरत भी है। महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत को प्रतिभा के पलायन को लेकर गंभीरता से सोचने और काम करने की जरूरत है। यह बेहद चिंता का विषय है। भारत से लगातार बौद्धिक वर्ग का पालयन पश्चिमी देशों की तरफ हो रहा है। वह वहां के विकास में

सहायक बनकर देश का नाम ऊंचा कर रहा है, लेकिन हमें तकनीकी और आर्थिक मोर्च पर आगे बढ़ना है तो गंभीरता से विचार करना होगा। इसमें जाने वालों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। हम अपने सुशिक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने में सहायक होने के बजाय अलग-अलग तरह की बाधाएं पैदा कर उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उस स्थिति में यह वर्ग देश से पलायन का रास्ता अपनाता है और यह सिलसिला लगातार जारी है। इस वर्ग को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। इससे योग्यता के मापदंड पीछे छूट जाते हैं। नौकरी के साथ भारत में अब उच्च शिक्षा के लिए भी पलायन बढ़ रहा है। यह और भी चिंताजनक है। जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनमें से ज्यादातर नौकरी भी वहीं पर करेंगे। इसके अलावा हमारे देश में हर स्तर पर राजनीतिक दखलअंदाजी भी इसका बड़ा कारण है। देश में बड़ा मुकाम पाने के लिए आपको राजनीतिक शह की जरूरत होती है। इसके बिना आपका बहुत आगे बढ़ पाना आसान नहीं है, चाहे बात प्रशासन की हो या उच्च शिक्षा की। ऐसे में प्रतिभावान युवा कार्य संस्कृति के मामले में हमसे बेहतर पश्चिमी देशों का रुख कर रहा है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट-

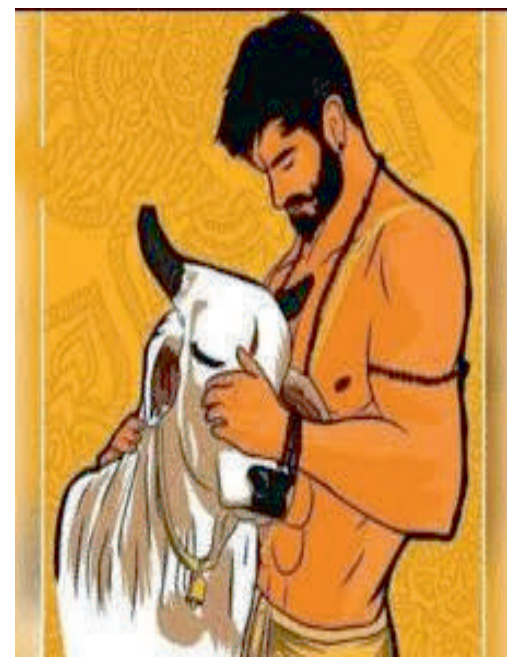

बच्चों को प्रतिबंधित करने वाली सोशल मीडिया की आयु सीमा बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है

विजय गर्ग

बच्चों को प्रतिबंधित करने वाली सोशल मीडिया की आयु सीमा बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है लेकिन शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा किशोरों को इसके संभावित नुकसान से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है ऑस्ट्रेलिया की सरकार 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करना चाहती है, और यह पता लगाने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तकनीक-प्रेमी किशोरों को, जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर बड़े हुए हैं, उन्हें वापस लॉग इन करने का तरीका जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वादा किया गया विनियमन, वर्तमान में विवरणों पर विरल है, ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के नीति निर्माता और माता-पिता इन प्लेटफार्मों के विकासशील दिमागों पर पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों से जूझ रहे हैं। यह वैश्विक बहस वर्षों से चली आ रही है, 2021 में फेसबुक (अब मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक) के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हाउगेन के दस्तावेज़ लीक होने के बाद चरम पर पहुंच गई, जिसमें दिखाया गया था कि कंपनी को पता था कि उसके उत्पाद लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। वर्षों बाद, अमेरिकी सांसद अभी भी शक्तिशाली बिग टेक कंपनियों को युवा उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह बनाए रखने के लिए संघीय विनियमन पर जोर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मामले को अपने हाथ में ले रहा है. प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इस वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने वाले नए कानून लाने का वादा किया, उन्होंने कहा कि सरकार कटऑफ के लिए 14 और 16 के बीच की सीमा पर विचार कर रही है। एक्स पर ₹माताओं और पिताओं₹ के लिए पोस्ट किए गए एक वीडियो में, अल्बानीज़ ने कहा कि वह चाहते हैं कि बच्चे ₹अपने उपकरणों से दूर और फ़ुटी फ़ील्ड पर आएं।₹ सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई सोशल-मीडिया आयु सीमा का समर्थन करते हैं, और इस विचार को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन अल्बानीज़ भी स्वीकार करते हैं कि वे अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करेगा। सरकार यह नहीं पहचानती है कि युवा प्रतिबंध किन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लागू होगा (क्या बच्चे व्हाट्सएप पर अपने माता-पिता को संदेश भेज सकते हैं? या यूट्यूब पर खान अकादमी के बीजगणित ट्यूटोरियल देख सकते हैं?)। यह प्रवर्तन (बिग ब्रदर-एस्क डिजिटल आईडी? बच्चों को और अधिक अपराधी बनाना, इस बार टिकटॉक खोलने के लिए?) पर विशेष विवरण प्रदान नहीं करता है। और ठोस नीतियों के अभाव में, इसे चुनावी वर्ष से पहले एक लोकप्रिय मुद्दे पर मतदान करने वाले माता-पिता के प्रति चिंता का संकेत देने वाले एक ठोस प्रस्ताव के रूप में नहीं देखना मुश्किल है - वास्तव में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी पूरा किए बिना। सिलिकॉन वैली से हजारों मील दूर, ऑस्ट्रेलिया बिग टेक के प्रभुत्व पर लगाम लगाने के प्रयासों में अग्रणी रहा है। डिजिटल गलत सूचना पर नकेल कसने के उद्देश्य से अलग प्रस्तावित कानून ने एलन मस्क को भी नाराज कर दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते सरकार को ₹फासीवादी₹ करार दिया था। (सरकार ने एक आतंकवादी हमले के हिंसक वीडियो पर मस्क के एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर मुकदमा दायर किया है, लेकिन अदालत में हार गई।) टेक दिग्गजों को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए राष्ट्र वर्षों से लड़ाई में लगा हुआ है। ऐसे समय में जब अन्य न्यायक्षेत्र ऐसी शक्तिशाली कंपनियों को लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुआयामी हमले सराहनीय हैं। लेकिन शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा किशोरों को इसके संभावित नुकसान से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। युवा लोगों ने समाधान खोजने में उल्लेखनीय कौशल दिखाया है - यहां तक कि 13 वर्ष से कम उम्र के लोग भी जिन पर अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म पहले से ही प्रतिबंध लगाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि सोशल मीडिया का उपयोग किशोरों के लिए स्वाभाविक रूप से फायदेमंद या हानिकारक नहीं है, लेकिन सख्त आयु सीमाएं किशोरों के परिपक्वता स्तर में व्यक्तिगत अंतर को नजरअंदाज करती हैं। दूसरे शब्दों में, 16 साल का हो जाना तुरंत नहीं बनता आप 14 साल के एक परिपक्व बच्चे की तुलना में डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने में अधिक सक्षम हैं। इस अनुभाग से और अधिक इंटेल इंटेल को सेना के लिए एमएफजी चिप्स के लिए पेंटागन से $3 बिलियन प्राप्त हुए; शेयरों में बढ़त डायची जापानी कंपनी दाइची लक्षित कैंसर दवाओं की खोज में अकेले जाना चाहती है जो बिडेन, बिडेन, जो इज़राइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने युद्ध पर बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार को अपडेट किया अमेरिका ने गाजा में हमलों को लेकर इजरायली सेना के प्रति निराशा व्यक्त की है अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि Google ने विज्ञापन स्टार्टअप AdMeld को खतरे के रूप में देखा और इसे खरीद लिया व्यापक आयु सत्यापन को ऑनलाइन लागू करने की प्रक्रिया गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देती है, जिसमें युवा उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी की पहचान करने से लेकर डिजिटल गुमनामी बनाए रखते हुए इंटरनेट को स्वतंत्र रूप से ब्राउज़ करने की उनकी क्षमता में कटौती तक शामिल है। डिजिटल समुदायों तक पहुंच को पूरी तरह से बंद करने से कुछ युवाओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लोगों की जीवनरेखा भी ख़राब हो सकती है। टिकटॉक, विशेष रूप से, स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक लोकप्रिय मंच के रूप में उभरा है, जिससे उन्हें एक ऐसा स्थान मिल गया है जहां वे बजट-अनुकूल व्यंजनों से लेकर नस्लवाद पर संबंधित प्रतिक्रियाओं तक सब कुछ साझा करते हैं। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्वदेशी युवा, जो अपनी कहानियों को पारंपरिक मीडिया में प्रतिबिंबित नहीं देख पाते, वे कम अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एलजीबीटीक्यू+ समर्थकों ने प्रतिबंध प्रभावी होने पर कमजोर समलैंगिक किशोरों के लिए कनेक्शन के संभावित नुकसान के बारे में इसी तरह की चिंता जताई है। अधिक मोटे तौर पर, तकनीकी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर करने से वे वेब के अंधेरे, यहां तक कि कम विनियमित कोनों में चले जाएंगे। फिर भी, सबूतों का बढ़ता समूह इस बात की ओर इशारा करता है कि युवा लोगों को नुकसान का एक बड़ा भंडार हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी किसी भी लिंक को हटाना पसंद करते हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि कानून निर्माता बच्चों को इन जोखिमों से बचाने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन जटिल, वैश्विक समस्याओं के लिए त्वरित समाधान बेचने से वास्तविक दुनिया के प्रभावी समाधानों के लिए आवश्यक कठिन नीतिगत कार्यों से ध्यान भटक जाता है। युवाओं को डिजिटल जीवन में भाग लेने से प्रतिबंधित करने में एक पीढ़ी बहुत देर हो चुकी है। वास्तविकता यह है कि आजकल किशोर बहुत अधिक ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, यह प्रवृत्ति महामारी के कारण तेज हो गई है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बच्चों को इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वयस्कों की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि यह हानिकारक न हो। नीति निर्माताओं को सोशल मीडिया कंपनियों को उनकी सेवाओं से होने वाले नुकसान, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने पर ध्यान देने की जरूरत है। वे यह मांग करके शुरुआत कर सकते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म उनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करें और अधिक बाहरी शोधकर्ताओं को जोखिमों की पहचान करने की अनुमति दें। उनकी सेवाओं को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इस पर डेटा साझा किए बिना, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए खतरों को संबोधित करने वाले समाधानों की सिफारिश करना कठिन है। कानून निर्माताओं को सोशल मीडिया कंपनियों की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो अपने उपयोगकर्ताओं को समझने, युवा लोगों के लिए अधिक रेलिंग बनाने और लागू करने के लिए काफी प्रयास करती हैं। तकनीकी कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म पर जोखिम कम करने की जिम्मेदारी डाले बिना, आयु सीमा को कुछ साल बढ़ाने से अगली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। बाढ़ के पानी को बाल्टी में डालने के बजाय, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाहर के नीति निर्माताओं को उगलने वाले नलों को बंद कर देना चाहिए।

शेयर मार्केट और म्युचुअल फंड से बैंकों को नुकसान? अब नए तरीके से जुटाएंगे पैसे

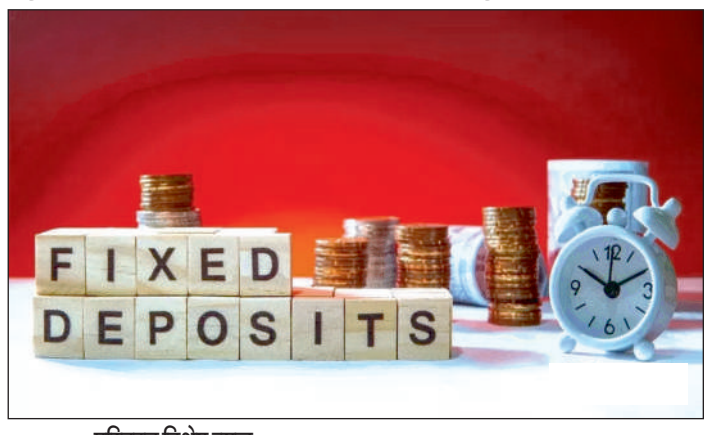

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के बैंकिंग सिस्टम के सामने नकदी की तंगी की समस्या हो सकती है। लोन ग्रोथ के मुकाबले डिपॉजिट ग्रोथ काफी कम है। बैंक अमूमन डिपॉजिट को ही कर्ज के रूप में देकर ब्याज से मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में अगर उनके पास जमा से ज्यादा लोन की डिमांड रहेगी कैश का संकट पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए बैंक पैसे जुटाने के विकल्प तलाश रहे हैं।

नई दिल्ली। बैंक सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ के चलते काफी परेशान हैं। दरअसल, ज्यादातर लोग अच्छे रिटर्न की चाह में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का रुख कर रहे हैं। इससे बैंकों में पैसे जमा करने वालों की गिनती घट रही है, वहीं लोन लेने वाले अधिक है। ऐसे में बैंकों के सामने नकदी का संकट भी आ सकता है। यही वजह है कि बैंक अब बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

रेटिंग एजेंसी इकरा ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक बॉन्ड के जरिये 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि जुटा सकते हैं। यह बैंकों की ओर से बॉन्ड के जरिये जुटाई जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा राशि होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से करीब 85 प्रतिशत बॉन्ड सरकारी बैंकों की ओर से जारी किए जाएंगे। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बॉन्ड की ज्यादा हिस्सेदारी रहेगी। एजेंसी का कहना है कि नकदी की समस्या और जमा के मुकाबले कर्ज वितरण में ज्यादा वृद्धि के कारण बैंकों के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों से धन जुटाना आवश्यक हो गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों ने बॉन्ड के जरिये एक लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक बैंक बॉन्ड के जरिये 76,700 करोड़ रुपये जुटा चुके हैं। यह राशि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 225 प्रतिशत ज्यादा है।

एजेंसी का कहना है कि निजी क्षेत्र के बैंक अपना ऋण-जमा अनुपात कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए चालू वित्त वर्ष में बॉन्ड के जरिये पैसा जुटाने में सरकारी बैंकों का वर्चस्व है।

85 हजार के पार जाकर लुढ़का सेंसेक्स, क्या बुधवार को बनेगा नया रिकॉर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती से प्रेरित घरेलू सूचकांक नई ऊंचाइयों को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक की ओर से दरों में कटौती और अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों ने वैश्विक निवेशक भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप घरेलू धातु शेयरों में लाभ हुआ है। अब नजरें अमेरिका के वित्तीय डेटा पर रहेंगी।

मुंबई। स्पष्ट संकेतों के अभाव में घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को दिनभर उतार-चढ़ाव का माहौल रहा। गिरावट के साथ दिन की शुरुआत करने वाला बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के दौरान 234.62 बढ़कर पहली बार 85 हजार के पार पहुंचा। लेकिन अंत में यह 14.57 अंक की गिरावट के साथ 84,914.04 अंक पर बंद हुआ। उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण दोपहर के समय यह 84,716.07 के निचले स्तर तक पहुंचा था।

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी पहली बार कारोबार के दौरान 26 हजार के पार पहुंचा। अंत में यह 1.35 अंक की तेजी के साथ 25,940.40 अंक के नए रिकार्ड स्तर पर जाकर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 72.5 अंक बढ़कर 26,011.55 के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंचा था।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदुस्तान यूनीलिवर, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक उच्च स्तर को बरकरार रखने में कामयाब नहीं रह सके। हालांकि, चीन में आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन उपायों से धातु क्षेत्र के शेयरों में तेजी रही।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती से प्रेरित घरेलू सूचकांक नई ऊंचाइयों को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक की ओर से दरों में कटौती और अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों ने वैश्विक निवेशक भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू धातु शेयरों में लाभ हुआ है।

उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद बाजार में सुस्ती रही, लेकिन प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे। इससे पता चलता है कि बाजार में तरलता प्रवाह मजबूत बना हुआ है। निवेशक भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी के प्रति आश्वस्त हैं।

प्रशांत ताप्से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, मेहता इक्विटीज लिमिटेड

इसके विपरीत एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली के कारण गिरावट देखी गई। निकट भविष्य में अमेरिकी फेड के नरम दृष्टिकोण और अक्टूबर में आरबीआइ की ओर से दरों में कटौती से प्रेरित विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से मजबूत प्रवाह बने रहने की उम्मीद है। व्यापक बाजारों की बात करें तो बीएसई मिडकैप में 0.21 प्रतिशत की तेजी रही और स्मालकैप में 0.04 प्रतिशत की गिरावट रही।

कच्चे तेल का मूल्य बढ़ने से 11 पैसे लुढ़का रुपया

घरेलू शेयर बाजारों में रहे उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में तेजी के कारण मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में 11 पैसे की गिरावट रही। अंतरबैंक मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 83.54 के स्तर पर खुला और अंत में यह 83.65 (प्रारंभिक) के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार को रुपया में डालर के मुकाबले दो पैसे की तेजी रही थी। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड का वायदा मूल्य 2.42 प्रतिशत 75.69 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

क्या पावर कंपनियों के शेयरों में दौड़ेगा करंट? बिजली क्षेत्र में 40 लाख करोड़ का होगा निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

बिजली की खपत बढ़ने से JSW एनर्जी टाटा पावर और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को तगड़ा फायदा मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इन कंपनियों के शेयरों में 16 से 25 फीसदी तक की तेजी आ सकती है। उसने इन तीनों कंपनियों को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म का दावा है कि 2035 तक इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा सेंटर बिजली की मांग को बढ़ावा देंगे।

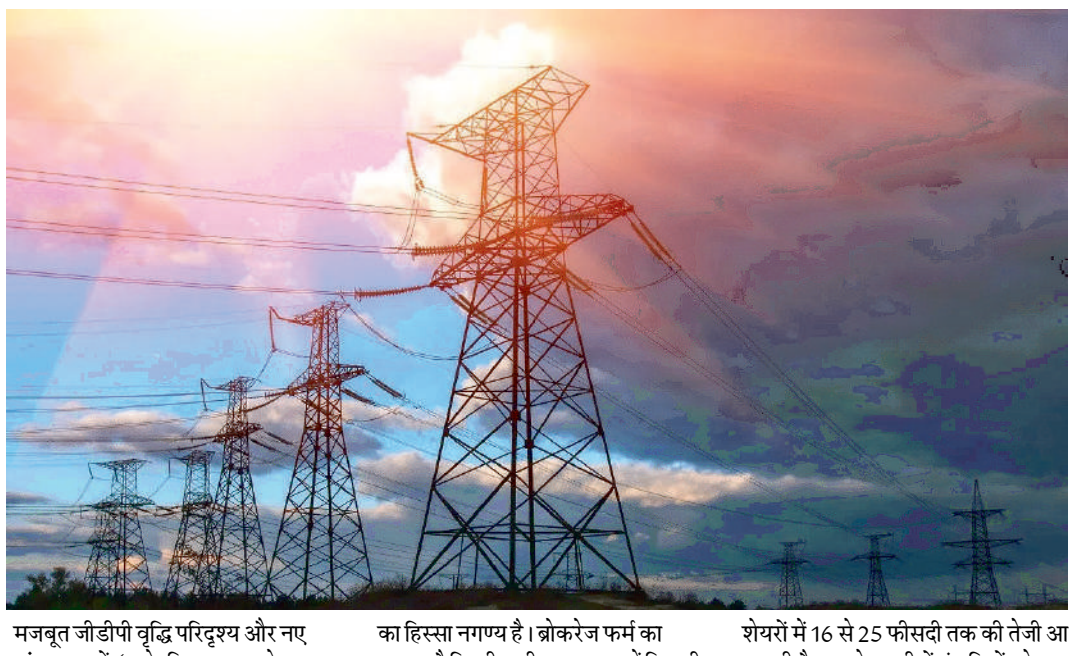

नई दिल्ली। अगले एक दशक के दौरान भारत के बिजली क्षेत्र में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है। इनमें से जहां 34 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय में खर्च होंगे, वहीं बाकी पैसे उत्पादन, ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग पर लगाए जाएंगे। यह बात ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत एक अनूठा केस बनकर उभरा है, जहां वास्तविक जीडीपी/प्रति व्यक्ति वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विद्युतीकरण जैसे सकारात्मक धाराएं मौजूद हैं। इससे आने वाले सालों में बिजली की मांग काफी अधिक बढ़ सकती है।

बिजली की खपत-मांग में होगा इजाफा

रिपोर्ट में कहा गया, भारत के लिए मजबूत जीडीपी वृद्धि परिदृश्य और नए मांग चालकों (इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर, विद्युतीकरण) के उभरने से हमारा मानना है कि भारत में बिजली की खपत अगले दशक में सात प्रतिशत से अधिक (वर्तमान में 8-9 प्रतिशत) बढ़ सकती है।'

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2035 तक, इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा सेंटर भारत में बिजली की मांग में एक तिहाई वृद्धि को बढ़ावा देंगे। आज भारत में बिजली की मांग में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और डेटा सेंटर का हिस्सा नगण्य है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि चीन की तरह भारत में बिजली की खपत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि अगले दशक में भारत में 6.5-7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

किन कंपनियों को मिल सकता है फायदा

बिजली की खपत बढ़ने से JSW एनर्जी, टाटा पावर और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को तगड़ा फायदा मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इन कंपनियों के शेयरों में 16 से 25 फीसदी तक की तेजी आ सकती है। उसने इन तीनों कंपनियों को BUY रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज फर्म ने एनटीपीसी को न्यूट्रल रेटिंग दी है। एनटीपीसी के बारे में उसका कहना है कि इसमें तेजी की संभावनाएं सीमित हैं। दरअसल, एनटीपीसी की सब्सिडियरी NTPC ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपये का IPO लाने वाली है। इस स्थिति में हो सकता है कि निवेशक NTPC की बजाय इसकी क्लीन एनर्जी कंपनी में पैसे लगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं।

तिरुपति मंदिर में अब 'नंदिनी' के घी से बनेंगे लड्डू, 26 लाख किसानों की रोजी-रोटी बन चुके ब्रांड की कहानी

तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और दूसरी चीजों की मिलावट के चलते काफी बवाल मचा हुआ है। इसके चलते मंदिर में लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी को बदल दिया गया है। अब तिरुपति मंदिर के लड्डू नंदिनी ब्रांड के घी से बनेंगे। इस ब्रांड का दक्षिण में वही दबदबा है जो उत्तर में अमूल और मदर डेयरी का है।

नई दिल्ली। भगवान विष्णु को समर्पित तिरुपति मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्पकला चलते श्रद्धालुओं के बीच काफी मशहूर है। लेकिन, बीते कुछ दिनों से तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और दूसरी चीजों की मिलावट पर हंगामा मचा है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने खुद तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट की पुष्टि करने वाली लैब रिपोर्ट को सार्वजनिक किया।

सरकार ने भारी विवाद के बीच लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी को बदल दिया। अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) लड्डुओं के लिए 'नंदिनी' ब्रांड का घी इस्तेमाल करेगा। आइए जानते हैं कि नंदिनी ब्रांड में क्या खास है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी।

हर घर की पहचान नंदिनी

उत्तर भारत में डेयरी ब्रांड के तौर पर अमूल या फिर मदर डेयरी मशहूर हैं। दक्षिण में यही रुतबा 'नंदिनी' को हासिल है। यह कर्नाटक का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है, लेकिन इसका दबदबा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में भी है। नंदिनी ब्रांड को कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (KMF) संभालता है। अगर नंदिनी नाम की बात करें, तो ये पौराणिक कथाओं से आया है। यह भगवान राम के वंश यानी रघुवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम था।

नंदिनी की शुरुआत कैसे हुई

कर्नाटक सरकार ने साल 1974 में कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (KDCC) का गठन किया। इसका मकसद वर्ल्ड बैंक के डेयरी प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना था। एक दशक बाद यानी साल 1984 में इसका नाम कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर दिया गया। यही वो वक्त था, जब कंपनी ने 'नंदिनी' दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट बाजार में उतारे। फिर यह ब्रांड कर्नाटक और आसपास के राज्यों में डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए सबसे मशहूर नाम बन गया।

हर रोज 28 करोड़ का भुगतान

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (Karnataka Milk Federation) हर रोज 24,000 गांवों के 26 लाख किसानों से करीब 86 लाख किलो दूध खरीदती है। वह दूध उत्पादक किसानों को ज्यादातर डेली पेमेंट कर देती है। फेडरेशन का दावा है कि वह रोजाना करीब 28 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। दरअसल, दूध बेचने ज्यादातर छोटे किसान होते हैं। उन्हें हर रोज पैसे मिल जाने से अपनी जरूरतों के साथ जानवरों के चारे का बंदोबस्त करने में भी सहूलियत होती है।

नंदिनी नाम से 148 प्रोडक्ट

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी नाम से करीब डेढ़ सौ प्रोडक्ट बेचता है। इनमें दूध, दही, बटर, पनीर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क के अलावा चॉकलेट, रस्क, कुकीज, ब्रेड और आइसक्रीम भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में KMF का कुल टर्नओवर 19,784 करोड़ था। इसकी तुलना अमूल ब्रांड के मालिक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से करें, तो उसका टर्नओवर करीब 61,000 करोड़ था।

नंदिनी-अमूल का विवाद

अमूल और नंदिनी घनघोर प्रतिद्वंद्वी हैं। पिछले साल अमूल ने कर्नाटक के रिटेल मार्केट में उतरने का फैसला किया, तो बवाल मच गया। दरअसल, इन दोनों कंपनियों के बीच एक अलिखित समझौता है कि वे एकदूसरे के मार्केट में नहीं उतरेंगी, जब तक वे वहां की डिमांड पूरी करने में सक्षम हैं। हालांकि, अमूल ने दावा किया कि बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में दूध की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। कर्नाटक के सियासी दलों ने इसे 'दक्षिण में उत्तर की घुसपैठ' तक करार दे दिया था।

शादी और त्योहारी सीजन से पहले क्या है सोने-चांदी का भाव, चेक कीजिए लेटेस्ट प्राइस

सोने और चांदी की कीमतों पर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर दिख रहा है। बाजार और व्यापारी अब फेड अधिकारियों के प्रमुख भाषणों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसमें फेड चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल का भाषण और यूएस जीडीपी और कोर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीई) इंडेक्स डेटा शामिल हैं जो सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों को नई दिशा प्रदान करेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 76,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। बाजार सूत्रों के अनुसार, सोमवार को कीमती धातु छह महीने के अंतराल के बाद 76,950 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि धातु ने इससे पहले इस साल 22 मार्च को 76,950 रुपये का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की ताजा मांग के कारण चांदी भी 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर मजबूत हुई।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 76,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। इस बीच, दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोने (24 कैरेट) की कीमतें 76,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रही थीं। दूसरी ओर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 248 रुपये या 0.33 प्रतिशत बढ़कर 74,543 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए।

दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध भी 469 रुपये या 0.53 प्रतिशत बढ़कर 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। वैश्विक स्तर पर, सोना 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,658.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

सोने के भाव पर क्या है एक्सपर्ट की राय

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹मंगलवार को सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि कई अमेरिकी फेडरल रिजर्व सदस्यों ने ब्याज दरों में और अधिक कटौती के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है।"

वहीं, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के कमोडिटीज एंड करेंसीज के एवीपी मनीष शर्मा ने कहा, ₹कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने से सोने में लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की गई, जो अमेरिकी आर्थिक अनिश्चितता को लेकर चिंताओं और यूएस फेड द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदों से प्रेरित है।₹

फेड चेयरपर्सन के भाषण पर नजर

चीन में सकारात्मक भावनाओं के बीच हाजिर बाजार में सोना नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने 2024 के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दरों में कटौती और प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की।

आनंद राठी शेयर्स के शर्मा ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने भी बुलियन की कीमतों को समर्थन देना जारी रखा। उन्होंने कहा कि बाजार फेड अधिकारियों के प्रमुख भाषणों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसमें फेड चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल का भाषण और यूएस जीडीपी और कोर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीई) इंडेक्स डेटा शामिल हैं, जो सप्ताह के दौरान कीमतों को नई दिशा प्रदान करेंगे।

10 हजार फर्जी कंपनियां, सरकारी खजाने को 10 हजार करोड़ का चूना

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जरिए टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चल रही है। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 16 अगस्त को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी अभियान में फर्जी फर्मों और टैक्स चोरी की रकम का खुलासा हुआ है। सरकार फर्जी जीएसटी पंजीकरण की जांच के लिए सख्त कार्रवाई कर रही और अधिक फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है।

नई दिल्ली। टैक्स अधिकारी सरकारी खजाने को चूना लगाने वाली फर्जी कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहे हैं। इसमें करीब 10,700 कंपनियों का पता चला है, जिन्होंने सरकारी खजाने को 10,179 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एसोचैम के एक कार्यक्रम में बोलते हुए शशांक प्रिय ने यह भी कहा कि भविष्य में टैक्स अधिकारी नए करदाताओं पर उनकी रिस्क प्रोफाइल के आधार पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, ₹हमें सिस्टम के दुरुपयोग पर बहुत दुख होता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी तरीकों का उपयोग करना होगा कि टैक्स चोरी करने वाले रोका जाए। हम आगे चलकर यह पाबंदी भी लगा सकते हैं कि कोई कंपनी एक महीने में कितनी इनवॉइस जारी रख सकती है।₹

सीबीआईसी अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार फर्जी जीएसटी पंजीकरण की जांच के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है और अधिक फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 16 अगस्त को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर अधिकारियों ने 67,970 जीएसटीआईएन की पहचान की है। इनमें से 59 प्रतिशत जीएसटीआईएन या 39,965 का 22 सितंबर तक सत्यापन हो चुका है।

शशांक प्रिय ने कहा, ₹27 प्रतिशत गैर-मौजूद पाए गए हैं। यह प्रतिशत पिछले अभियान की तुलना में लगभग समान है। हमने 10,179 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। 2,994 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोका गया है। साथ ही, 28 करोड़ रुपये की वसूली (22 सितंबर तक दूसरे अभियान में) की गई है।₹

16 मई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के बीच फर्जी पंजीकरण के खिलाफ पहले अभियान में, जीएसटी पंजीकरण वाली कुल 21,791 संस्थाओं का वजूद ही नहीं पाया गया। पिछले साल पहले विशेष अभियान के दौरान 24,010 करोड़ रुपये की संदिग्ध कर चोरी का पता चला था।

संस्कारशाला: आज के भारतीय माता-पिता के लिए मोबाइल फोन - मदद या खतरा?

डॉ. अंकुर शरण

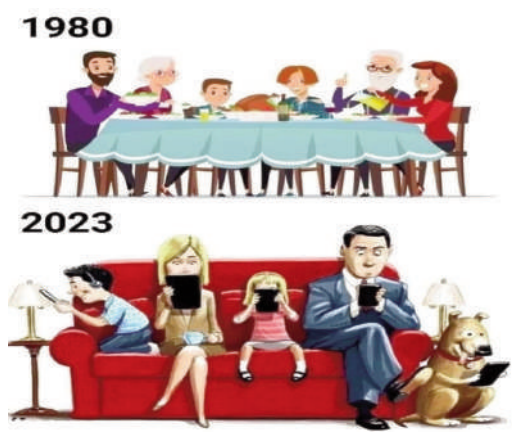

आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हर किसी की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह न केवल हमारे कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में सहायता करता है, बल्कि हमारे बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन जहाँ एक ओर यह नई ऊँचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

मोबाइल फोनः मदद या खतरा?

आज के माता-पिता के लिए मोबाइल फोन दो धारी तलवार की तरह है। एक ओर, मोबाइल फोन बच्चों को नई तकनीकों से रूबरू कराता है, उन्हें वैश्विक ज्ञान और शिक्षण संसाधनों से जोड़ता है। कई ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म्स और ऐप्स ने बच्चों के लिए सीखने को आसान और मजेदार बना दिया है।

लेकिन इसके विपरीत, बच्चों का अधिक समय मोबाइल पर बिताना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अत्यधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल न केवल उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डाल रहा है, बल्कि उनकी सामाजिक ज़िम्मेदारी, रचनात्मकता और व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया की चकाचौंध में डूबे बच्चे असली दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और संवाद कौशल घट रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने से बच्चे आभासी दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। इससे उनमें हीन भावना, अवसाद, और आत्मसम्मान की कमी जैसे मानसिक विकार विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

सामाजिक दुनिया से दूरी

आजकल के बच्चे अधिकतर समय अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे वे परिवार और दोस्तों के साथ कम वक्त बिता रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे असली दुनिया में सामाजिकता का महत्त्व समझने में असफल हो रहे हैं। वे समाज से कट रहे हैं और वास्तविक दुनिया में संवाद करने की कला खोते जा रहे हैं। यह स्थिति उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बन रही है, जिससे भविष्य में उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

माता-पिता की ज़िम्मेदारी

आज के भारतीय माता-पिता के सामने यह एक बड़ा सवाल है कि वे अपने बच्चों को मोबाइल फोन के सही और सीमित उपयोग के लिए कैसे प्रेरित करें। सबसे पहले, माता-पिता को अपने बच्चों के लिए एक संतुलित दिनचर्या बनानी चाहिए, जिसमें पढ़ाई, खेल, और सामाजिक गतिविधियाँ शामिल हों। मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल शिक्षण सामग्री और सीमित मनोरंजन के लिए ही किया जाना चाहिए।

माता-पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे खुद अपने मोबाइल फोन का उपयोग बच्चों के सामने कैसे करते हैं। बच्चों के लिए माता-पिता उनके पहले आदर्श होते हैं, और वे उन्हीं की नकल करते हैं। इसलिए माता-पिता को अपने व्यवहार में भी जिम्मेदारी दिखानी होगी।

मोबाइल फोन आज के दौर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका अतिरेक हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल सकता है। यह माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को तकनीक की अच्छाईयों से अवगत कराते हुए उन्हें इसके दुष्प्रभावों से बचाएँ। सही दिशा-निर्देश और समय प्रबंधन के साथ, मोबाइल फोन हमारे बच्चों के लिए सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, न कि एक खतरा।

यह लेख माता-पिता को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि तकनीकी प्रगति के इस युग में बच्चों के लिए संतुलन और अनुशासन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।

बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और परिवार के जीवन को संतुलित बनाने के लिए निम्नलिखित कुछ विशेष सुझाव और तकनीकें अपनाई जा सकती हैं:

1. समय सीमा निर्धारित करें

बच्चों के मोबाइल उपयोग के लिए समय सीमा तय करें। सुनिश्चित करें कि उनका स्क्रीन टाइम एक दिन में सीमित हो।

2. परिवारिक गतिविधियाँ

परिवार के साथ मिलकर खेलों या अन्य गतिविधियों की योजना बनाएं, जैसे पिकनिक, बोर्ड गेम्स या कला और शिल्प। इससे बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे।

3. नियमित शारीरिक गतिविधियाँ

बच्चों को खेलकूद, जिमनास्टिक या दौड़ने के लिए प्रेरित करें। ये गतिविधियाँ न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, बल्कि उन्हें मोबाइल से भी दूर रखेंगी।

4. सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी

बच्चों को सामाजिक कार्यक्रमों, जैसे क्लब्स या सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका सामाजिक कौशल विकसित होगा।

5. डिजिटल डिटॉक्स

सप्ताह में एक दिन ₹डिजिटल डिटॉक्स₹ का पालन करें, जिसमें सभी परिवार के सदस्य बिना मोबाइल के समय बिताएँ। इस दिन को खास पारिवारिक गतिविधियों के लिए समर्पित करें।

6. परिवार के साथ भोजन

परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करते समय मोबाइल फोन को दूर रखें। यह न केवल बातचीत को बढ़ावा देगा, बल्कि परिवार के बंधन को भी मजबूत करेगा।

7. किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें

बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यह उन्हें मानसिक रूप से व्यस्त रखने का एक अच्छा तरीका है और मोबाइल की आवश्यकता को कम करेगा।

8. सकारात्मक रोल मॉडल बनें

माता-पिता को भी मोबाइल का उपयोग सीमित करना चाहिए। जब बच्चे अपने माता-पिता को ऐसा करते हुए देखेंगे, तो वे भी इसी तरह का व्यवहार अपनाएँगे।

9. रचनात्मक गतिविधियाँ

बच्चों को कला, संगीत, या नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और वे मोबाइल से दूर रहेंगे।

10. संवाद बढ़ाएँ

बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें। उनके दिनभर की गतिविधियों, विचारों और भावनाओं के बारे में चर्चा करें। यह उन्हें मोबाइल से दूर रखने में मदद करेगा और पारिवारिक संबंध मजबूत करेगा।

इन सुझावों को अपनाकर आप न केवल बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और संतुलित परिवारिक जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं।

लेखक का परिचयः

डॉ. अंकुर शरण विभिन्न संस्थाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ कई अभियानों का प्रबंधन किया है और साहित्य उत्सवों का आयोजन किया है। बच्चों की मनोविज्ञान पर उनकी गहरी नजर है। वे वैश्विक एनजीओ परिसंघ (Global Confederation of NGOs) के सह-संस्थापक हैं और एक समाजसेवी के रूप में समाज को बेहतर कल के लिए जागरूकता और धैर्य के माध्यम से सेवा दे रहे हैं। यह लेख उन बच्चों और परिवारों को समर्पित है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण ही इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर बनाता है।

डाल लदे ट्रक में लगी आग

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : डाल लदे ट्रक में लगी आग। लाखों रुपए की डालें जल गईं। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचाया ।कटक के फुलनाखारा के स्टेट हाईवे क्रमांक 60 अमेनाकुड स्ट्रीट पर डाल लदे ट्रक OD 34 P 3647 में अचानक आग लग गई ।ट्रक कटक से नुआहाट जा रहा था तभी यांत्रिक खराबी के कारण उसमें आग लग गई। इससे लाखों रुपये की डालें जलकर राख हो गयीं। आग की गति इतनी तेज थी कि ओडशपुर और नियाली की दो दमक सेनाओं को आग तक पहुंचने में सुबह पांच से सात बजे के बीच दो घंटे लग गये। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। स्थानीय लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। आमतौर पर चर्चा है कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

तामीलनाडु पॉन ब्रोकर एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन

परिवहन विशेष न्यूज

चेन्नई ।दिनांक 24सितम्बर 2024मंगलवार सुबह 11बजे तामीलनाडु सतर्कता वह भष्ट्राचार रोक थाम वह निगरानी विभाग के सयुक्त निदेशक सन्तोशकुमार आई पी एस से उनके चैन्नई कार्यालय मे तामीलनाडु पॉन ब्रोकर एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी तेजानन्द वह तामीलनाडु पॉन ब्रोकर ऐवम ज्वेलर्स एसोसिएशन मदुरवाईल फिरका तालुक के अध्यक्ष जबरचन्द बैम्ब वह तामीलनाडु पॉन ब्रोकर ऐवम ज्वेलर्स एसोसिएशन मदुरवाईल फिरका तालुक सचिव निर्मलकुमार सोलओढाकर शिष्टाचार मुलाकात की इस मुलाकात मे तामीलनाडु पॉन ब्रोकर ऐवम ज्वेलर्स व्यापारियों कि समस्याओं कि वर्तमान स्थिति के बारे मे चर्चा कि सन्तोशकुमार आई पी एस ने तामीलनाडु गिरवी एवं ज्वेलर्स व्यापारियों कि समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

आरईसी ने चौथे री-इन्वेस्ट के दौरान 1.12 लाख करोड़ के लिए आरई डेवलपर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

परिवहन विशेष न्यूज

गांधीनगर/गुरुग्रामः विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू और एक प्रमुख एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड ने गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) के दौरान आरई डेवलपर्स के साथ लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

समझौता ज्ञापनों में सौर और पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, सौर और पवन राउंड द क्लॉक (आरटीसी) परियोजना, फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) बिजली, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बेस), पंप स्टोरेज, हाइड्रोपावर, ग्रीन अमोनिया/हाइड्रोजन, सोलर सेल/मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और अन्य अभिनव तकनीकों पर आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इकोसिस्टम सहित संबंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा, आरईसी शीर्ष रेटेड ऑफटेकर वाले सीएंडआई सेगमेंट के लिए डेवलपर्स द्वारा रिन्यूएबल परियोजनाओं पर विचार करने के लिए भी खुला है।

आरईसी ने इस आयोजन में भाग लिया और कई प्रमुख हितधारकों और अग्रणी आरई डेवलपर्स के साथ व्यापारिक चर्चा की। आरईसी की योजना 2030 तक देश की स्थापित गैर जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से 500 गीगावाट तक पहुंचाने की यात्रा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का है। आरईसी ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा ऋण पुस्तिका को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाने के लिए 'शपथ पत्र' के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है। इससे 2030 तक अक्षय ऊर्जा का हिस्सा मौजूदा 8% से बढ़कर 30% हो जाएगा, क्योंकि आरईसी की ऋण पुस्तिका 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह शपथ पत्र आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस द्वारा श्री प्रहलाद जोशी, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया।

शपथ पत्र सौंपने के बाद, आरईसी के सीएमडी ने आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए केन्द्रीय मंत्री से मान्यता प्राप्त की।

विरोध और आतिशी खड़ाऊ

चुनाव में उम्मीदवार का विरोध,
कुछ इस तरह किया जा रहा है।
किसानों का ट्रैक्टर फैक्टर बन,
उम्मीदवार पर चढ़ाया जा रहा है।
ऐसा तो होना नहीं होना चाहिए,
गुस्से पर भी कंट्रोल होना चाहिए।
इधर आतिशी भी बड़ा सही बोली है,
खडाऊ की तरह केजरीवालजी की
कुर्सी,
बगल में रखकर चलाऊंगी सरकार।
यह तो हम भी सोच रहे यहीं हैं दरकार।
अब उन्हें आतिशी बल्लेबाजी करना है।
सपने में भी केजरीवाल से आगे
अब कभी उन्हें नहीं निकलना है।
मौका नहीं है उनके पास गिरने का,
उन्हें तो संभल-संभल कर ही चलना है।
अरविंद कह रहे ईमानदारी साबित
करने के बाद ही इस कुर्सी पर बैठेंगे।
अब पता नहीं आगे क्या हो?
नहीं तो जेल की कोठरी में ही लेटेंगे।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

आंध्रप्रदेश तेलंगाना में रक्तदान की अद्भुत सेवा दे रहे रक्तवीर मनोज जी जैन को रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन अयोध्या उत्तरप्रदेश ने राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान से किया सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

आंध्रप्रदेश तेलंगाना में 81 बार रक्तदान कर चुके रक्तवीर मनोज जी जैन को रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन एवं मेजर ध्यानचंद खेल उत्थान सीमित उत्तरप्रदेश में ओलंपिक व अर्जुन अवॉर्ड मुख्य अतिथि श्री अशोक ध्यानचंद जी ,लावारिस लाशों के वारिस पद्मश्री मोहम्मद शरीफ जी , अयोध्या महानगर महापौर श्री गिरीश जी त्रिपाठी ,अयोध्या जिला पंचायत श्रीमती रोली सिंह जी , अयोध्या विधानसभा विधायक श्री वेदप्रकाश गुप्ता जी एवं रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन अयोध्या के अध्यक्ष श्री आकाश जी गुप्ता ने मोमेंटो , प्रशस्ति पत्र , राम नाम का गलपटा देकर सम्मानित किया !रक्तवीर मनोज जी जैन खुद रक्तदान करते है और दुसरो को भी रक्तदान के प्रति जागरूक करके रक्तदान करवाते है ! इस विशाल कार्यक्रम में भारत वर्ष के लगभग सभी राज्यों से रक्तवीर, रक्तविरंगनाओ को भी सम्मानित किया ! इस कार्यक्रम में रक्तदान की जागरूकता के लिए रक्तदान शिविर भी लगाया गया जिसमें लगभग सभी अवार्डीयो ने अपना रक्तदान किया !

गांधी जी के तीन बंदर और आज की वास्तविकता: समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी : अंकुर

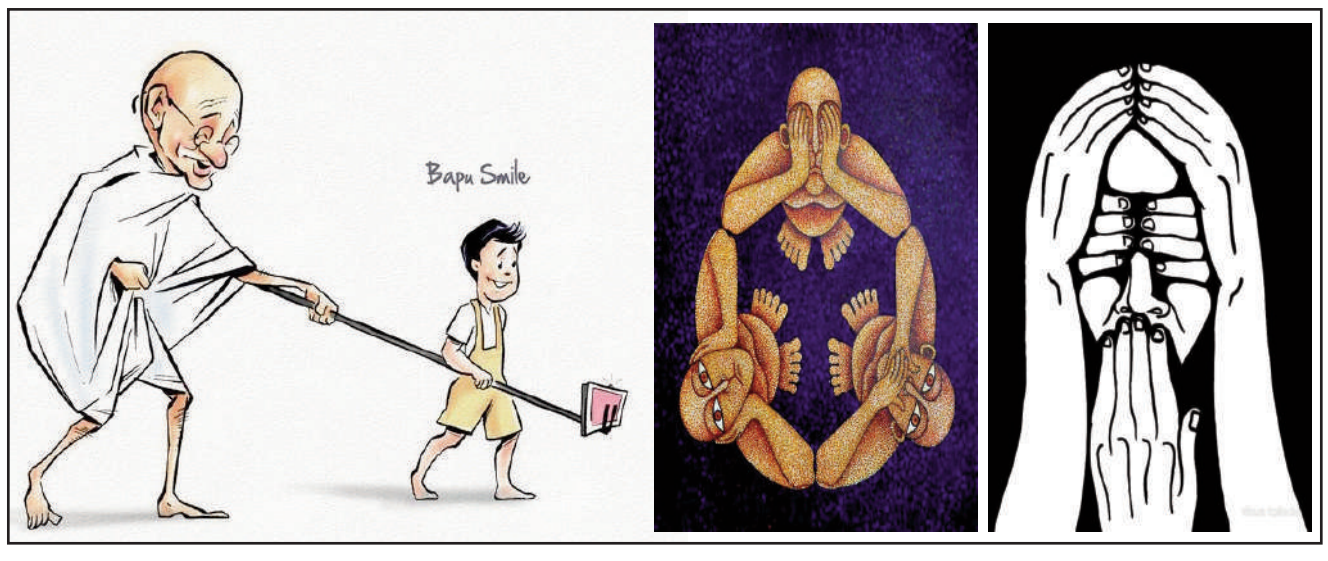

गांधी जी के तीन बंदरों की कहानी हम सबने सुनी है – बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन क्या आज के समय में हम इस सीख का सही अर्थ समझ पा रहे हैं? आधुनिक समाज में ये तीन बंदर मानो एक नया रूप ले चुके हैं। आज हम बुराई देखकर आंखें बंद कर लेते हैं – कचरा सड़कों पर पड़ा हो या गलत काम होते हुए दिखे, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है: ₹हमें क्या, ये काम तो सरकार या नगर निगम का है।₹

हमारी उदासीनता ने हमें मूक दर्शक बना दिया है। हम देखते हैं कि समाज में गंदगी फैली है, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। और अगर बोलने का प्रयास करें, तो हमें डर सताता है कि कहीं हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसी तरह, यदि कुछ गलत सुनाई दे, तो हम कान बंद कर लेते हैं, जैसे कुछ सुना ही न हो। यह स्थिति हमें मूक, बधिर और अंधा बना रही है।

क्या यही सीख हमने अपने समाज से ली है? क्या यही हमारा कर्तव्य है?

आज के दौर में हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें मूक दर्शक नहीं, बल्कि समाज के बदलावकारी (Change Makers) बनना है। हमें #VocalForLocalSafety का समर्थन करना चाहिए, जिसमें हम अपने समाज और अपने आस-पास की समस्याओं के प्रति सजग रहें और समाधान के लिए खुद आगे आएं।

अगर हम यह सोचते हैं कि केवल सरकार या नगर निगम ही हर समस्या का समाधान करेंगे, तो यह हमारी भूल है। समाज ने हमें अगर इस लायक बनाया है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज को कुछ वापस दें। यह सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम है।

हमें proactive बनकर खुद समस्याओं का हिस्सा बनने की बजाय उनके समाधान में योगदान देना होगा। चाहे वह सफाई अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण हो, सड़क सुरक्षा हो, या समाज के किसी भी अन्य पहलू पर सुधार की बात हो – हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।

इसलिए, अगर हम असली बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना होगा। आंखें बंद करने से समस्याएं खत्म नहीं होतीं, और कान बंद करने से अन्याय नहीं रुकता। हमें आंखें खोलनी होंगी, गलतियों को देखना होगा, सुनना होगा, और बोलना होगा। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठाइए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए, और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाइए।

अगर आज हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, तो भविष्य में यह समाज हमारे बच्चों के लिए और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए, अभी से शुरुआत करें – एक जिम्मेदार नागरिक बनें और अपने आस-पास के बदलाव का हिस्सा बनें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023